RNI No. :BIHHIN/2013/53084

संपादक

अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक

अखिलेश कुमार, 9431089053

राजनीतिक संपादक

प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

संपादकीय सलाहकार

राजीव कुमार सिंह 9431210181

कॉन्सेप्ट एडिटर

अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

प्रबंधक

अविनाश कुमार 8287266244

विधि सलाहकार

वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट

बिहार ब्यूरो

अनूप नारायण सिंह 9546224277

क्राइम ब्यूरो

एसएन श्याम

मुख्य संवाददाता

सोनू सिन्हा,9431006189

आशीष कुमार

जिला ब्यूरो

बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316

भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार, (ब्यूरो चीफ), 9334194515, 7677093032

समस्तीपुर : राजेश कुमार

चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993

कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता 9973077043

सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)

सहरसा : आशीष झा

बिहार-झारखंड : अभिनव कुमार 7903292877

दिल्ली : एश्वर्या सिंह, स्वाति

ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)

मो.- 9431006107

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली मंदिर रोड़ नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से प्रकाशित व एस. एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर टोली, डीएन दास लेन, पटना-800 004,से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके लिए संपादक से सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक

डॉ. संजय मयूख

राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी भाजपा

जय जयराम सिंह

JJRS CONSTRUCTION PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 12, अंक : 08, अगस्त 2026, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

08 बांकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त भाजपा को करना चाहिए आत्ममंथन

संघर्ष से शिखर तक : बिहार के 10

खत्म नहीं होगा आरक्षण... 13

राजपूत राजनीति और आरजेडी ... 11

डेहरी डालमियानगर ईओ ... 14

जायज जेन-जी

अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि नई पीढ़ी को सुना जाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध तरीका है। हाल ही में जेन-जी आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान जो शिकायतें सामने आई हैं, वे जायज हैं। गुरुवार को जेन-जी से जुड़े एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान भागवत ने ये बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध करने वाले राष्ट्रविरोधी नहीं हैं। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी सहमति बनाने का माध्यम है। हालांकि, विपक्ष ने तंज किया कि उन्हें यह सलाह सरकार को भी देनी चाहिए और यह भी कि आंदोलनकारियों की मांग को इतनी देर से क्यों सुना गया। बहरहाल, भागवत ने माना कि बहुत संभव है कि विरोध के दौरान मुद्दों को लेकर विचारों की भिन्नता हो, लेकिन चर्चा के बाद ही किसी विषय पर सहमति बनती है। साथ ही माना कि आंदोलन का उद्देश्य सहमति बनाना होना चाहिए, न कि समाज में विभाजन पैदा करना। उन्होंने माना कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। यही वजह है कि छात्रों का गुस्सा सामने आ रहा है, जिसे संवाद से दूर करने की जरूरत है। साथ ही, सख्ती नहीं, बातचीत के जरिये अपनापन का अहसास कराना भी जरूरी है। यह भी कि जेन-जी और जेन-अल्फा की सोच पहले की पीढ़ियों से भिन्न है। पहले की पीढ़ी बड़ों की बात मान लेती थी, सवाल नहीं करती थी। लेकिन नई पीढ़ी सवाल करने के साथ ही तर्कसंगत जवाब की आकांक्षा रखती है। निस्संदेह, बहस से कई विचार सामने आते हैं। हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण होता है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि एक ही विषय के कई पहलू सामने आ सकते हैं। यह तय है कि विचार-प्रतिविचार के मंथन से नई दिशा व नई तस्वीर उभरती है। विरोध करना बुरा नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए। भागवत ने इस बात पर भी बल दिया कि विरोध-आंदोलन संविधान की मर्यादा के दायरे में होना भी जरूरी है। समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका लक्ष्य व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। साथ ही, संघ प्रमुख ने आरक्षण पर भी राय स्पष्ट की कि सामाजिक भेदभाव दूर करने तक आरक्षण की जरूरत होगी। लेकिन सवाल यह है कि इस सत्य से वाकिफ होने के बावजूद सरकारें क्यों टालमटोल का रवैया अपनाती हैं? यह संवादहीनता की स्थिति क्यों पैदा की जाती है? विडंबना यह है कि सरकारें तब जागती हैं जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। सरकारों को लोकतंत्र में प्रतिरोध के स्वरों का भी सम्मान करना है। लोकतंत्र का आधार जनमत है। जनमत को सुना जाना चाहिए। आमतौर पर नागरिक तब ही सड़कों पर उतरते हैं जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है। ऐसे में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और असहमति के स्वरों पर ध्यान देने की जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस को बताया जाए कि राष्ट्रविरोधियों और जायज मांगों के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को एक ही लाठी से नहीं हांका जा सकता। खासकर, जेन-जी पर शक्ति प्रयोग असंतोष को उग्र बनाना ही है। सत्ताधीशों को इस बात का भान होना चाहिए कि असहमति और शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति से लोकतंत्र जीवंत होता है। सत्ता की उदासीनता और उपेक्षापूर्ण रवैये से आंदोलन की जमीन तैयार होती है। कालांतर में हठधर्मिता से यह आक्रोश को ही बढ़ाता है। सत्ताधीशों को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में लोग अपनी बात सुनाने के लिए आंदोलन को विकल्प के तौर पर अपनाते हैं। ऐसे ही नीट प्रश्नपत्र मुद्दे पर समय रहते वे कदम पहले ही उठा लिए जाते, तो आंदोलन को व्यापक होने से टाला जा सकता था। अक्सर संवादहीनता की स्थिति में आंदोलन में राजनीतिक दल रोटियां सेंकने लगते हैं। निहित स्वार्थी तत्व इसमें अवसर तलाशने लगते हैं, जिससे आंदोलन की दिशा नियंत्रित नहीं रह सकती है।

अभिजीत कुमार
संपादक
9431006107
cbhindi.news@gmail.com

बांकीपुर उपचुनाव
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर पीके का कब्जा

राजकिशोर सिंह

जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत गए हैं. ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी. सभी 32 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर 64,151 वोट पाकर भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत गए हैं. भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले. पाटलिपुत्र की हार भाजपा के लिए केवल एक चुनावी झटका नहीं है. यह उस राजनीतिक आत्मविश्वास पर करारा प्रहार है, जिसने शायद पार्टी को यह विश्वास दिला दिया था कि बिहार में उसकी चुनावी मशीनरी अचूक है. जनता ने इस धारणा को नकार दिया है. इतिहास गवाही देता है कि साम्राज्य बाहर से कम, भीतर से अधिक टूटते हैं. यही कारण है कि हर बड़ी चुनावी हार के बाद असली लड़ाई विपक्ष से नहीं, पार्टी के भीतर शुरू होती है. सवाल रणनीति का उठता है, जवाबदेही की मांग होती है और नेतृत्व की परीक्षा शुरू होती है. भाजपा के सामने अब सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी ही राजनीतिक कहानी को बचाए रखना है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी प्रशांत किशोर की चुनौती का प्रभावी जवाब नहीं दे सकी? क्या स्थानीय नेतृत्व जमीनी संकेत पढ़ने में विफल रहा? क्या रणनीति वास्तविक जनभावना से कट चुकी थी?

बहरहाल, सबकी निगाहें अब बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी टिक गई होगी. चुनावी राजनीति का नियम साफ है कि जब जीत होती है तो नेतृत्व श्रेय लेता है, और जब हार होती है तो उसी नेतृत्व से कठिन सवाल पूछे जाते हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस हार को केवल स्थानीय घटना बताकर आगे बढ़ती है या फिर संगठन और नेतृत्व की व्यापक समीक्षा करती है. भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि उसने एक सीट गंवाई है. असली खतरा तब होगा, जब पार्टी इस संदेश को कम करके आंकेगी. भारतीय राजनीति में अनेक बार एक सीट की हार ने बड़े राजनीतिक बदलावों की भूमिका लिखी है. 1977 में कांग्रेस को भी शुरूआती झटकों ने चेताया था, 2004 में "इंडिया शाइनिंग" का आत्मविश्वास भी मतदाता के फैसले के सामने टिक नहीं पाया था.

पाटलिपुत्र की धरा पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फैसला एक सवाल छोड़ गया है, क्या भाजपा इसे चेतावनी मानेगी, या फिर इसे एक साधारण हार कहकर आगे बढ़ जाएगी? आने वाले महीनों में इसका जवाब केवल बयान नहीं, बल्कि पार्टी के

कायस्थ राजनीति में पीके के ताला

राजकिशोर सिंह

बिहार की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह कोई नहीं जानता है. जब राजनीतिक ऊंट दूसरी तरफ बैठता है, तो पुरानी करवट की चर्चा शुरू हो जाती है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने सूबे की सियासत में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विश्लेषक अपने-अपने स्तर से इन सवालों की व्याख्या कर रहे हैं. लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जिस बांकीपुर विधानसभा सीट पर कायस्थ जाति का दबदबा था, वह दबदबा क्या खत्म हो गया है? यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राजनीतिक पैरोकारों ने लाला (कायस्थ) की राजनीतिक सियासत में ताला लगा दिये गये. इस बदवाल के साथ ही बिहार की राजनीति में धीरे-धीरे कायस्थों का राजनीतिक प्रभाव कमजोर दिख रहा है. अब इस समाज से सिर्फ नाम मात्र के जनप्रतिनिधि ही बचे हैं. वरना, एक समय ऐसा भी था जब कायस्थ जाति के प्रबुद्ध राजनेताओं ने अपनी अद्भुत योग्यता, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ का लोहा बिहार से लेकर पूरे देश तक में मजबूती से मनवाया था.

इस सियासी इतिहास की शुरूआत देश की आजादी के दौर से करना बेहद जरूरी है. क्योंकि स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारतीय संविधान के निर्माण तक में कायस्थ समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है. जब संविधान बनाने की कवायद शुरू हो रही थी तो उसके अंतरिम अध्यक्ष बिहार के कायस्थ समाज से आने वाले डॉ सच्चिदानंद सिन्हा थे. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे. जो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे. यह भी कायस्थ थे और यह भी ताल्लुक बिहार से ही रखते थे.बिहार की राजनीति में कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद के बाद जब बिहार में पहले विधानसभा चुनाव हुआ तो 1952 के विधानसभा चुनाव में 21 विधायक कायस्थ जाति से चुनकर आए थे. यह संख्या उस समय बड़ी थी क्योंकि बिहार में तब 252 सीट पर ही चुनाव होते थे. मंडल और कमंडल की राजनीति के उभार, जातियों के समीकरण और दलों की टिकट वितरण नीति के कारण शहरी और बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में पहचाने जाने वाले इस समाज का राजनीतिक वजूद लगातार सिमटता गया है.

बिहार विधानसभा मंडल में कायस्थ जाति का दबदबा इतना ज्यादा था कि 1952 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष सर राजीव रंजन प्रसाद को बनाया गया था जो कायस्थ जाति से आते थे. वहीं, विधानसभा के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद बने थे. यही नहीं 1963 में केबी सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री भी बने और पांचवें मुख्यमंत्री के तौर पर महामाया प्रसाद का चुनाव हुआ था. यह दोनों राजनेता कायस्थ जाति से आते थे. वर्ष 1952 में 21 कायस्थ विधायक जीतने के बाद यह संख्या लगातार कम होती चली गई. साल 1962 के चुनाव में 11 विधायक चुनकर सदन पहुंचे थे. वहीं 1969 के चुनाव में सिर्फ 7 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे और 1972 के चुनाव में यह आंकड़ा घटकर केवल 4 विधायकों पर सिमट गया. इसके बाद 1977 में 9 विधायक चुने गए, लेकिन 1980 में यह संख्या 6, 1985 में 5, 1990 में 4 और 1995 में 7 रही. 2000 और 2005 में केवल 4-4 विधायक ही चुने जा सके. 2010 में यह संख्या 03, 2015 में 04, 2020 में 03, 2025 में 2 और अंततः 2026 में यह प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम स्तर पर केवल 1 रह गया.

वर्तमान राजनीति में कायस्थों के उत्थान के रुप में देखा जाए तो बांकीपुर के पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद नीतीन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. 2025 में कायस्थ विधायको की संख्या 2 हुआ करती थी. अब एक रह गई है वो सिकटा के जदयू विधायक समृद्ध वर्मा के रूप में है. वैसे पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ जाति से आते है. यानि बिहार से लोकसभा में मात्र एक सांसद है. वहीं, बिहार विधान परिषद में भाजपा के संजय मुयख है जो इसी समुदाय से आते है. कुल मिलाकर भाजपा का कोर वोट कायस्थ के महज दो ही नेता है. विधानसभा में भाजपा की स्थिति शून्य है. ग्लोबल कायस्थ कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं कि 5000 साल का इतिहास है, जिसमें कायस्थ समुदाय के लोगों ने बराबर समाज की अगुवाई की, चाहे प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत के नवनिर्माण, स्वाधीनता संग्राम, क्रांतिकारियों का इतिहास, अध्यात्म सभी क्षेत्रों में कायस्थों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया. एक लंबी फेहरिस्त है. जिसको जाति के दायरे में बांधने की जरूरत नहीं है. कह सकते हैं कि पूरे राष्ट्र को गौरव दिलाने में आगे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज इस समाज की घटती हुई हिस्सेदारी चिंता का विषय है. जरूर सिस्टम को इस पर ध्यान देना चाहिए. एक ऐसे राष्ट्रवादी समूह जिसकी विद्वता, योग्यता, सदैव राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है. वह उपेक्षित ना रह जाए, इतिहास के हासिये पर उसे धकेल ना दिया जाए, सिस्टम को ध्यान देना होगा.

वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पाण्डेय कहते हैं कि देखिए, पहले जो राजनीति होती थी उसमें योग्य लोगों की बहुत मान्यता थी. योग्यता, क्षमता, दक्षता, इसको माना जाता था. इसलिए योग्य लोगों को चुना जाता था. उसमें कायस्थ जाति आती थी. धीरे-धीरे कायस्थों ने राजनीति में रुचि लेनी कम कर दी. दूसरी वजह यह है की राजनीति में पिछड़ा उभार हुआ है. पिछड़ा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने लगा. उनके जनप्रतिनिधि चुनकर आने लगे, उस वजह से भी कायस्थों के साथ-साथ सामान्य जाति के लोग भी राजनीति में जगह कम होती गई. अभी राजनीति में संघर्ष ज्यादा है. ऐसे में कायस्थ जाति के लोग फिट नहीं बैठते हैं. बीच के समय में जब धन बल और बाहुबल का जोर था, वह कायस्थों को सूट नहीं कर रहा था. उसके बाद से कायस्थ राजनीति से दूर होते गए. ना वह पैसा खर्च कर सकते थे ना गुंडे मवाली खरीद सकते थे. इसलिए उन्होंने नौकरी, शिक्षा आदि चीजों पर ध्यान केंद्रित कर लिया. उन्होंने आगे कहा कि पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े थे, उनके परिवार के लोग राजनीति करते थे. धीरे-धीरे वह पीढ़ी विलुप्त होती गई. देखिए, केबी सहाय और महामाया प्रसाद जैसे लोग कायस्थ होने की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे. दोनों अपनी योग्यता के कारण मुख्यमंत्री बने थे. केवी सहाय बहुत ही काबिल प्रशासनिक आदमी थे. महामाया प्रसाद सिंह को जाइंट किलर कहा जाता है. उन्होंने बड़े-बड़े दिग्गजों को उनके घर में हराया. इसलिए राजनीति में उनकी पूछ ज्यादा थी और मुख्यमंत्री बने.

फैसले देंगे. यदि यह हार आत्ममंथन का कारण बनी तो भाजपा मजबूत होकर लौट सकती है; यदि नहीं, तो यह परिणाम बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरूआत भी साबित हो सकता है. बांकीपुर सीट पटना के शहरी इलाके में मौजूद है और इस सीट को भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. इस सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे. इस सीट से उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी भाजपा के विधायक थे.

आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे और इस वजह से इसके नतीजे पर कई लोगों की नजर रही है. दिल्ली के साथ ही साथ देश के कई इलाकों में युवाओं और स्टूडेंट्स के आंदोलन के ठीक बाद इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे. इन उपचुनावों को प्रदर्शनों के असर के नजरिए से भी देखा जा रहा है. इस शहरी सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 34 फीसदी वोटिंग हुई थी. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41.35 फीसदी मतदान हुआ था. तब भाजपा के नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को करीब 52 हजार मतों से हराया था. इस सीट से भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर और राजद ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा था. प्रशांत किशोर के चुनाव में उतरने से यह सीट हाई प्रोफाइल हो गई. कांग्रेस पार्टी ने अघोषित तौर पर प्रशांत किशोर का समर्थन किया है. बांकीपुर सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे. उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन प्रशांत किशोर ने अंतिम समय में चुनाव में उतरने से मना कर दिया था.

न्होंने तब कहा था कि 'यह उनकी पार्टी का फैसला था कि बाकी सीटों पर ध्यान देना जरूरी है.' बांकीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था, "मैं बांकीपुर उपचुनाव लड़ने की ज़िम्मेदारी

आमतौर पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जाता है, लेकिन इस बार बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में उतरे और इस वजह से इसके नतीजे पर कई लोगों की नजर रही है. दिल्ली के साथ ही साथ देश के कई इलाकों में युवाओं और स्टूडेंट्स के आंदोलन के ठीक बाद इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे. इन उपचुनावों को प्रदर्शनों के असर के नजरिए से भी देखा जा रहा है. इस शहरी सीट पर हुए उपचुनाव में करीब 34 फीसदी वोटिंग हुई थी. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41.35 फीसदी मतदान हुआ था.

को उसी लक्ष्य की तरफ एक कदम मानता हूं. नवंबर 2025 में हजारों और लाखों लोग जन सुराज के विचारों और प्रयासों से जुड़े थे. अगर हम जीते तो इससे न सिर्फ. यह आंदोलन मजबूत होगा, बल्कि बिहार में बदलाव की सोच को भी नई ताकत मिलेगी." जन सुराज पार्टी साल 2025 के चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी. पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसके 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे. इस सीट पर भाजपा की ओर से घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने अंतिम समय में पारिवारिक कारण बताते हुए 10 जुलाई को अपना नामांकन वापस ले लिया था. दरअसल उनके मात-पिता चारा घोटाला के अभियुक्त थे और वर्तमान में जमानत पर हैं. जबकि कुछ घंटे पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बांकीपुर में अभिषेक कुमार बंटी के लिए लोगों से वोट मांग रहे थे. इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया. नीरज सिन्हा साल 2006 से भाजपा के सदस्य हैं और दो बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं. इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशांत किशोर का कहना था कि जनता के पास अब विकल्प आ गया है तो भाजपा को अब उम्मीदवार नहीं मिल रहा है.

चुनाव रणनीतिकार के तौर पर राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद विधानसभा चुनाव लड़े हैं. इसलिए बांकीपुर का यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की भी बड़ी परीक्षा रही है. हाल के छात्र आंदोलनों के बाद हुए इस उपचुनाव को कई राजनीतिक विश्लेषक युवाओं के बदलते राजनीतिक रुझान से भी जोड़कर देख रहे हैं. वैसे, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ चुका है और यहां 31 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है. प्रशांत किशोर 19,324 हजार वोटों से चुनाव जीत चुके हैं. भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा. यह हार ऐसे समय में आई है जब 2006 से लगातार नितिन नवीन इस सीट से विधायक रहे थे और उनसे पहले 1995 से उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक रहे थे. इसी साल भाजपा ने नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. दूसरी ओर, पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है. ऐसे में राजधानी पटना के वीवीआईपी इलाके माने जाने वाले बांकीपुर के मतदाताओं की ओर से भाजपा को नकारे जाने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं. इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं कि भाजपा की हार के पांच बड़े कारण क्या-क्या हैं?

पीके का आया असमिया डॉक्टर पर दिल

@ राजकिशोर सिंह

बिहार की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) ने जीत हासिल कर ली है. उपचुनाव की मतगणना में बीते तीन अगस्त को प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों के अंतर से हराकर जीत का परचम लहरा दिया. इसके साथ ही 31 साल पुराना भाजपा का किला ढहाए गये. राजनीति में जितनी चर्चा उनकी रणनीति की होती है, उतनी ही जिज्ञासा उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी रहती है. प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा सार्वजनिक मंचों से दूर रखते हैं. हालांकि, समय-समय पर उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी इस राजनीतिक यात्रा में उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास की भूमिका बेहद अहम रही है. प्रशांत किशोर की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं. उनका संबंध मूल रूप से असम के गुवाहाटी से है. ब्राहम्ण प्रशांत किशोर की पत्नी कायस्थ जाति से हैं. आपको बता दें कि 'दास' उपनाम असम में कई समुदायों, जैसे कायस्थ, कलिता और केवट समुदाय के लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है. केवल उपनाम के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति तय नहीं की जा सकती है. चुनावी शपथपत्र के अनुसार, डॉ. जाह्नवी दास नई दिल्ली स्थित अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में सीनियर एडवाइजर के पद से जुड़ी रही हैं. प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मुलाकात जाह्नवी दास से उस समय हुई थी, जब वे संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े हुए थे. उस समय दोनों एक यूएन समर्थित पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम कर रहे थे. शुरूआती बातचीत पूरी तरह कामकाज तक सीमित थी. दोनों सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं पर चर्चा करते थे. धीरे-धीरे यह पेशेवर रिश्ता दोस्ती में बदला और फिर दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे. प्रशांत किशोर के अनुसार, शुरूआत में दोनों के बीच केवल काम की बातें होती थीं. समय के साथ बातचीत का दायरा बढ़ा और दोनों ने महसूस किया कि वे जीवन भर साथ रह सकते हैं. इसके बाद प्रशांत किशोर ने अपने परिवार से इस रिश्ते की चर्चा की. परिवार की सहमति मिलने के बाद दोनों ने शादी कर ली. उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि यह शादी पूरी तरह परिवारों की सहमति से हुई थी. प्रशांत किशोर हमेशा अपनी पत्नी और बेटे को सार्वजनिक जीवन से दूर रखते आए हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह जानबूझकर परिवार के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वे चाहते हैं कि राजनीति का असर उनके निजी जीवन पर न पड़े. उनका मानना है कि राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन को अलग-अलग रखना बेहतर होता है. प्रशांत किशोर और डॉ. जाह्नवी दास का एक बेटा है, जिसका नाम दैबिक है. प्रशांत किशोर कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपनी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास के योगदान की चर्चा कर चुके हैं. उनका कहना है कि अगर उनकी पत्नी घर और परिवार की जिम्मेदारियां नहीं संभालतीं, तो शायद वह राजनीति में इतना समय नहीं दे पाते. कई बार पीके ने यह भी कहा है कि आज मैं राजनीति कर पा रहा हूं तो इसके पीछे मेरी पत्नी का सबसे बड़ा योगदान है. उन्होंने मुझे घर-परिवार की हर जिम्मेदारी से मुक्त रखा है. कभी समय न देने की शिकायत नहीं की.

आपको बता दें कि, 25 अगस्त 2024 को पटना में आयोजित एक महिला सम्मेलन के दौरान प्रशांत किशोर ने पहली बार अपनी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास को सार्वजनिक मंच पर लोगों से परिचित कराया था. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने परिवार को प्राथमिकता दी और उनके राजनीतिक जीवन को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि घर की पूरी जिम्मेदारी जाह्नवी ने संभाली, जिससे वह लगातार बिहार में जन सुराज अभियान चला सके.

बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है. यहां लगभग 14 प्रतिशत कायस्थ मतदाता हैं, जो सबसे बड़ा सामाजिक समूह माना जाता है. चूंकि, प्रशांत की पत्नी डॉ. जाह्नवी दास गुवाहटी के कायस्थ जाति से हैं, तो माना जा सकता है कि पत्नी के गोल्डन चाम ने बांकीपुर की जीत को मुक्कमल कराने में अहमियत साथ-साथ है.

बांकीपुर में जाति समीकरण देखें तो कायस्थ लगभग 14%, मुस्लिम लगभग 14%, यादव लगभग 12%, वैश्य लगभग 9%, चंद्रवंशी लगभग 9%, दलित-महादलित लगभग 8%, भूमिहार लगभग 8%, ब्राह्मण लगभग 7%, राजपूत लगभग 7%, कुर्मी लगभग 5% और कुशवाहा लगभग 3% फीसदी हैं.

इन्हीं सामाजिक समीकरणों के कारण यह सीट वर्षों तक भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है. लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को यहां 58 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे. हालांकि, इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक रणनीति, जनसंपर्क और स्थानीय मुद्दों के सहारे भाजपा की परंपरागत बढ़त को चुनौती दी और 31 वर्षों का चुनावी इतिहास बदल दिया.

बांकीपुर में जिस समय मतदान के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था उसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी. 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान सीजेपी के आंदोलनकारियों पर जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया तो इसकी गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई दी. इसके बाद देश के कई हिस्सों समेत 22, 23 और 25 जुलाई को बिहार के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए. 25 जुलाई को 'बिहार बंद' बुलाया गया और सीवान ज़िले में आंदोलनकारियों पर कार्रवाई के दौरान एके-47 से फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ.

बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ लोगों की नाराजगी का भी दावा किया जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए सही फैसला नहीं था. इसका असर सिर्फ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है. बांकीपुर पहला चुनाव था, इसलिए इस नाराजगी का सीधा असर यहां के नतीजों में दिखाई दिया. बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा की हार की एक वजह मतदान प्रतिशत के बदलते पैटर्न के तौर पर सामने आ रही है. भाजपा कार्यकताओं के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा में कुल 422 मतदान केंद्र हैं. इनमें से 250 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां भाजपा का कोर वोटर माना जाता है. पहले इन बूथों पर विपक्ष को बेहद कम वोट मिलते थे, लेकिन इस बार इन 250 मतदान केंद्रों पर करीब 8 फीसदी कम मतदान हुआ.

बांकीपुर में जिस समय मतदान के लिए चुनाव प्रचार चल रहा था उसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी. 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दौरान सीजेपी के आंदोलनकारियों पर जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया तो इसकी गूंज देश के कई हिस्सों में सुनाई दी. इसके बाद देश के कई हिस्सों समेत 22, 23 और 25 जुलाई को बिहार के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए. 25 जुलाई को 'बिहार बंद' बुलाया गया और सीवान ज़िले में आंदोलनकारियों पर कार्रवाई के दौरान एके-47 से फायरिंग का एक वीडियो भी वायरल हुआ. इस दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कई आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया. जेपी आंदोलन के बाद ऐसा पहली बार देखा गया जब स्टूडेंट्स राजभवन या सीएम सचिवालय तक पहुंच गए थे. ये सारा इलाका बांकीपुर सीट में ही आता है. ीजेपी के प्रदर्शनों ने इस चुनाव में भी असर डाला है. साथ ही भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के 26 साल के युवक भरत भूषण तिवारी की 17 जून को कथित पुलिस एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी. भोजपुर के एसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया था, "पुलिस टीम ने खुद और लोगों की सुरक्षा के लिए गोली चलाई थी, जो भरत भूषण के पांव में लगी थी." हालांकि भरत तिवारी के परिजनों और पुलिस ने इस दावे को खारिज किया और इस घटना को सोची-समझी साज़िश बताया था. काफी-कुछ होने के बाद भरत तिवारी मामले में न्यायिक आयोग गठित करने के बाद भी एक्शन नहीं हो रहा था और इसी बीच उनके परिजनों ने पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी. सम्राट चौधरी ने इस मामले में काफी समय बाद एक्शन लिया, एसटीएफ के जवान को काफी समय बाद गिरफ़्तार किया गया. हालांकि ये भी अफवाहें उड़ीं की भरत तिवारी के परिजन प्रशांत किशोर के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन इस मामले ने जनता की भावनाओं को झंझोड़ दिया.

वहीं लगभग 50 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां विपक्ष का प्रभाव रहा है और राजद को बढ़त मिलती रही है. इस बार इन केंद्रों पर 2025 की तुलना में करीब 7 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ. दावा किया जा रहा है कि राजद का एम-वाई (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक भी बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर के पक्ष में गया, जिससे उनके समर्थकों की सक्रियता साफ दिखाई दी. यह कहने में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं माना जाएगा कि राजद का माई समीकरण खंड-खंड हो गया है. वर्ष 1995 से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज की जीत ने राज्य की राजनीति में नई चचाओं को जन्म दे दिया है. शुरूआती राउंड से ही बढ़त बनाए हुए प्रशांत किशोर हर चरण के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करते नजर आ रहे थे. 'स्कूल बैग' चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर लगातार बढ़त हासिल कर रहे थे. वहीं भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ता अंतर पीके के लिए निर्णायक बढ़त दे दिया है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर चलती रही और मुकाबले में काफी पीछे रह गई.

जातीय समीकरण ने भी बांकीपुर उपचुनाव में अहम रोल अदा किया है. माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भूमिहार समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज था. बांकीपुर में भूमिहार मतदाता करीब 7 प्रतिशत हैं और दावा किया जा रहा है कि इनमें से लगभग 60 प्रतिशत वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गए हैं. वहीं, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कुर्मी समाज में भी नाराजगी रही. यहां 5 प्रतिशत से अधिक कुर्मी मतदाता हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं. इसके अलावा, नीतीश कुमार का 'चुप्पा वोटर' मानी जाने वाली महिला मतदाताओं का 50 प्रतिशत से अधिक समर्थन भी प्रशांत किशोर के खाते में गया. नीतीश कुमार की अपील और प्रशांत किशोर द्वारा एआई वीडियो का मुद्दा उठाने का भी असर स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है.. दावा है कि जदयू का वोट पूरी तरह भाजपा में ट्रांसफर नहीं हो सका है.

राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अन्य सामाजिक वर्गों में भी सेंध लगायी है. जानकारों के मुताबिक, कायस्थ मतदाता भाजपा का कोर वोटर माना जाता है. हालांकि इसमें बड़ी टूट नहीं हुई, लेकिन 5 से 10 प्रतिशत तक वोट खिसकने का दावा किया जा रहा है. इसके अलावा राजपूत, अति पिछड़ा और दलित समुदाय के मतदाताओं का भी एक हिस्सा प्रशांत किशोर के पक्ष में गया, जिसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिल रहा है. भाजपा की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद जनमत का बदलना इस बात का संकेत है

कि पार्टी को पहले से अंदेशा था कि प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला कठिन हो सकता है. यही वजह रही कि एक विधानसभा सीट के लिए पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों के साथ-साथ एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेताओं को प्रचार में उतारा. डोर-टू-डोर कैंपेनिंग भी की गई, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मतदाता पहले ही अपना मन बना चुके थे. जातीय समीकरणों के बीच कई समुदायों ने अपनी नाराजगी मतदान के जरिए जाहिर की, जिसका असर अंतिम परिणाम में साफ दिखाई दिया.

बांकीपुर सीट पर वर्ष 2006 से नितिन नवीन विधायक थे. उनके भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनाया गया जिस कारण यह सीट रिक्त हुई और उपचुनाव हुआ. भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बनने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को अपना 'बॉस' कहा था लेकिन अब पीएम मोदी के बॉस के इलाके में ही भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है. करीब 1.30 लाख मतों वाले इस हाई-प्रोफाइल उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे, हालांकि मुख्य मुकाबला जन सुराज, भाजपा और राजद के बीच ही सिमटा हुआ रहा है. मतगणना के हर राउंड के साथ बदलते आंकड़े इस चुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में स्थापित करते रहे हैं. बांकीपुर विधानसभा सीट वर्षों से भाजपा का मजबूत गढ़ रही है. ऐसे में यदि अंतिम परिणाम में यह सीट भाजपा के हाथ से निकल गई है, तो इसे पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर के लिए यह प्रदर्शन उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और जनाधार के विस्तार का अहम संकेत माना जा रहा है.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अब गठबंधन सरकार में जदयू 'छोटे भाई' की भूमिका में आ चुका है. चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि जदयू मैदान में नहीं के बराबर थी और भाजपा अकेले मैदान में थी. अन्य सहयोगी दल लोजपा (रामविलास), हम और रालोमो की उपस्थित भी खानापूर्ति भर रही. 35 फीसदी से कम मतदान होना भी भाजपा के खिलाफ गया क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान जो उम्मीदवार बदले गए उससे गलत संदेश गया. प्रशांत किशोर मैदान में न होते तो वोटिंग प्रतिशत 24 फीसदी भी हो सकता था. चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखा गया कि प्रशांत किशोर सिर्फ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बना रहे थे. प्रशांत किशोर के कानूनी मामलों को सम्राट चौधरी ने मुद्दा बनाया, और वो सरकार के कामकाज की बात करते रहे, दूसरी ओर बांकीपुर का पूरा इलाका काफी समृद्ध है. बांकीपुर इलाके में विधायक, सांसद, जज और वकीलों के घर हैं. एक तरह से ये इलाका काफी शिक्षित और समृद्ध है तो इस दौरान प्रशांत किशोर की सम्राट चौधरी को निशाना बनाने की रणनीति ने भी काम किया. उन्होंने कभी भी नितिन नवीन या किसी और वरिष्ठ नेता को अपने भाषणों में ज़िक्र नहीं किया. उन्होंने जो भी अटैक किया सम्राट चौधरी पर ही किया. अपने भाषणों में वो सम्राट चौधरी को करप्ट और

क्रिमिनल बताते रहे.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर प्रशांत किशोर को बधाई देते हुए लिखा, "लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है. मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ." इधर, सम्राट सरकार में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भाजपा ने हमेशा से अपनाया है. हम कभी भी विपक्ष के लोगों की तरह ठीकड़ा चुनाव आयोग या इवीएम पर नहीं फोड़ते हैं. लोकतंत्र में हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं. पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार की गहन समीक्षा करेगी. ये बिहार की यही धरती है, जहां अभी 6 महीने पहले 202 सीटें हमने जीती थीं.' बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव और बांकीपुर के भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा भी अपने बुथ पर प्रशांत किशोर से कम वोट हासिल हुआ है.

बांकीपुर के लिए भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था. हालांकि, अगले ही दिन अभिषेक ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया गया था. इस सीट से बिहार भाजपा के कई वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उम्मीदवार एकदम नए चेहरे को बनाया गया. इस सीट पर कायस्थ समुदाय का अच्छा खासा वोट है और अजय आलोक जैसे नेता भी उम्मीदवारी की दौड़ में थे लेकिन भाजपा ने अचानक उम्मीदवार ही बदल दिया. इसी बीच एक भाजपा नेता की ओर से ये बयान दिया गया कि इस सीट से कोई भी जीत जाएगा. इससे भाजपा के वोटरों में एक भाव गया कि उन्हें 'टेकेन फॉर ग्रांटेड' लिया जा रहा है. एक आशंका ये भी है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके साथ के नेताओं ने इस सीट पर जीत के लिए मेहनत नहीं की. कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने भाजपा की कमजोरियों को उजागर किया है.

दरअसल, पीके की ये जीत एक सिंबोलिक है और इसके आगे प्रशांत किशोर पैन इंडिया अपनी छवि बनाने के बारे में सोचेंगे. विपक्ष चाहे तो उनको पंजाब और यूपी चुनाव में एक एंटी भाजपा चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार में ले जा सकता है. मतदान से पहले बिहार पुलिस ने रात दो बजे 64 लोगों को गिरफ़्तार किया था. इसके बाद प्रशांत किशोर ने सीनियर एसपी कार्तिकेय के शर्मा के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की. बहरहाल, अभी वक़्त बताएगा कि प्रशांत किशोर की जीत आगे किस रणनीति का हिस्सा बनकर उभरता है लेकिन फिलहाल भाजपा के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा सकता है.

बहरहाल, प्रशांत किशोर की जीत के नायक बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी मनोज भारती, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी, पूर्व डीजी आर के मिश्रा, हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व एडीजी जयप्रकाश सिंह, अनूप मैथिल, आदित्य मोहन, वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार तिवारी, जर्नलिस्ट नाजिम अली, अभय कुमार सिंह और हौसला अफजाई करने वाली ऊजार्वान्वित डॉ जहान्वी दास को भी भुलाया नहीं जा सकता है. जिन्होंने जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के साथ लम्बे अर्से से जुड़कर अपनी मजबूत कंधा को लगाये रखा. बांकीपुर चुनाव में यूट्यूबर्स पत्रकारों का आकलन बड़े-बड़े समीक्षक पर भारी पड़ा है. मेनस्ट्रीम के अधिकांश पत्रकार भाजपा को बढ़त बता रहे थे. वही 95% जमीनी यूटयूबर्स प्रशांत किशोर के पक्ष में एक पक्षीय लहर बता रहे थे.

बांकीपुर में बीजेपी का किला ध्वस्त भाजपा को करना चाहिए आत्ममंथन

बिहार की राजनीति में नए अध्याय की शुरूआत!

अखिलेश कुमार

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत केवल एक सीट का परिणाम नहीं है। यह बिहार की राजनीति में बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी है। जिस सीट को भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहीं जन सुराज ने पहली बड़ी चुनावी सफलता दर्ज कर दी। यह परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपना पूरा चुनाव अभियान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व और भाजपा सरकार के खिलाफ केंद्रित रखा था। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रशांत किशोर ने इसे स्थानीय उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे बिहार के नेतृत्व का सवाल बनाया। उन्होंने लगातार कहा कि यदि बांकीपुर बदलेगा तो बिहार की राजनीति भी बदलेगी। अब जीत के बाद स्वाभाविक है कि वे इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व के खिलाफ जनादेश के रूप में पेश करेंगे। यह उनका राजनीतिक नैरेटिव है।भाजपा के लिए यह हार कई सवाल छोड़ती है। यदि पार्टी अपने सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरी गढ़ को भी नहीं बचा सकी, तो संगठन, उम्मीदवार चयन, स्थानीय असंतोष और चुनावी रणनीति पर गंभीर समीक्षा करनी होगी। विशेष रूप से तब, जब शीर्ष नेतृत्व ने इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया था।

हालांकि, किसी एक उपचुनाव को पूरे बिहार का अंतिम जनादेश नहीं माना जा सकता। उपचुनावों पर स्थानीय परिस्थितियों, कम मतदान, उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता और चुनावी रणनीति का भी गहरा प्रभाव होता है। पर ये भी सच है की सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री काल का यह पहला चुनाव था।

पर इस परिणाम को सामान्य उपचुनाव की तरह खारिज करना आसान नहीं होगा। पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने उस सीट पर जीत हासिल की है, जहाँ भाजपा का लगभग तीन दशक का दबदबा रहा। इससे जन सुराज को राजनीतिक वैधता मिलेगी और विपक्ष को भी यह संदेश मिलेगा कि भाजपा को उसके गढ़ में चुनौती दी जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रशांत किशोर जीत गए, बल्कि यह है कि क्या बांकीपुर का संदेश पूरे बिहार में दोहराया जाएगा। यदि आने वाले महीनों में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही रुझान दिखाई देता है, तो यह परिणाम बिहार की राजनीति में वास्तविक बदलाव की शुरूआत माना जाएगा। लेकिन यदि यह असर केवल बांकीपुर तक सीमित रह जाता है, तो इसे एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में ही देखा जाएगा। इतना तय है कि बांकीपुर के परिणाम ने बिहार की राजनीति में एक नया राजनीतिक केंद्र बना दिया है। अब भाजपा को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और प्रशांत किशोर को यह साबित करना होगा कि बांकीपुर की जीत अपवाद नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक परिवर्तन की शुरूआत है।

विकास वैभव : एक आईपीएस अधिकारी से आगे, जनविश्वास की पहचान

अनूप नारायण सिंह

बिहार में यदि पिछले दो दशकों के चर्चित और जनविश्वास अर्जित करने वाले आईपीएस अधिकारियों की सूची बनाई जाए तो उसमें आईपीएस विकास वैभव का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। एक ऐसे पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अपनी कार्यशैली, ईमानदारी, संवेदनशीलता और नवाचार के बल पर प्रशासनिक सेवा को केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज निर्माण का माध्यम भी बनाया।अपने पुलिस सेवा के दौरान विकास वैभव अनेक चुनौतीपूर्ण अभियानों का हिस्सा रहे। बगहा क्षेत्र में डाकुओं के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया हो, रोहतासगढ़ किले को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कराने का अभियान, गया स्थित महाबोधि मंदिर विस्फोट कांड की जांच अथवा पटना के गांधी मैदान में हुए आतंकी मामले में शामिल आतंकियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई—इन सभी घटनाओं ने उन्हें एक सक्षम और परिणामोन्मुख पुलिस अधिकारी के रूप में स्थापित किया। कठिन परिस्थितियों में शांत, तथ्यपरक और पेशेवर नेतृत्व उनकी सबसे बड़ी पहचान रही है।लेकिन विकास वैभव की सबसे बड़ी पहचान केवल एक सफल आईपीएस अधिकारी की नहीं है। लगभग पाँच वर्ष पूर्व उन्होंने "छी३'२ क्ल्लर२स्त्र१ी इँ१ (मिलकर प्रेरित करें बिहार)" अभियान की शुरूआत की। समय के साथ यह पहल बिहार के सबसे बड़े गैर-राजनीतिक सामाजिक अभियानों में शामिल हो गई, जिससे लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इस मंच का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि शिक्षा, नवाचार, युवाओं का मार्गदर्शन, उद्यमिता, सांस्कृतिक गौरव और विकसित बिहार के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें किसी दल या विचारधारा का बंधन नहीं है। इसके कार्यक्रमों में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी आते हैं, विपक्ष

के नेता भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, शिक्षाविद भी, उद्योगपति भी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी। यह अभियान किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लोगों की सहभागिता का मंच बन चुका है। विकसित बिहार का सपना किसी दल विशेष का नहीं, बल्कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों की सामूहिक आकांक्षा है।

हाल के दिनों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए एक राजनीतिक बयान में आईपीएस विकास वैभव और एक विधायक का नाम जोड़ते हुए यह आरोप लगाया गया कि यह अभियान किसी विशेष व्यक्ति के आर्थिक सहयोग से संचालित होता है। यह एक राजनीतिक आरोप है, जिसका अब तक कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। दूसरी ओर, इस बयान के बाद राज्य के अनेक सामाजिक, बौद्धिक और नागरिक समूहों ने इसका विरोध दर्ज कराया और अभियान की गैर-राजनीतिक प्रकृति का समर्थन किया। लोकतंत्र में आरोप लगाना राजनीतिक अधिकार है, लेकिन किसी सामाजिक पहल की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने से पहले ठोस साक्ष्य अपेक्षित होते हैं।विकास वैभव की प्रशासनिक कार्यशैली का सबसे चर्चित प्रयोग जनता दरबार है। मगध रेंज के आईजी के रूप में उन्होंने ऐसी व्यवस्था विकसित की, जिसमें आम नागरिक सीधे जोनल आईजी के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। इसकी प्रेरणा से कई जिलों में पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर पर भी जनता दरबार आयोजित होने लगे। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि लोगों की शिकायतें केवल सुनी ही नहीं जातीं, बल्कि उनके समाधान की निगरानी भी होती है।आज यह मांग उठने लगी है कि यदि मगध रेंज में यह मॉडल सफल हो सकता है तो इसे पूरे बिहार में संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने का इससे बेहतर माध्यम शायद ही कोई हो सकता है।विकास वैभव की लोकप्रियता का कारण केवल उनकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि उनका व्यवहार, उनकी सादगी, संवाद की शैली और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी है। उन्होंने यह साबित किया है कि एक पुलिस अधिकारी वर्दी के भीतर रहते हुए भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है।बिहार को ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता है, जो केवल कानून लागू न करें, बल्कि समाज में विश्वास, प्रेरणा और भागीदारी का वातावरण भी तैयार करें। विकास वैभव की यात्रा यही संदेश देती है कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसरोकार यदि प्रशासन की आधारशिला बन जाएँ, तो सरकारी सेवा भी जनआंदोलन का रूप ले सकती है।आज जब सार्वजनिक जीवन में विश्वास का संकट बढ़ता दिखाई देता है, तब विकास वैभव जैसे अधिकारी यह भरोसा जगाते हैं कि निष्ठा, संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ काम करने वाले लोग व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी।

संघर्ष से शिखर तक : बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी की प्रेरक राजनीतिक यात्रा

अनूप नारायण सिंह की कलम से

बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते‌ङ्ग बल्कि लोगों का भरोसा जीतते हैं।

ऐसा ही एक नाम है — मिथिलेश कुमार तिवाग्री।

गोपालगंज की मिट्टी से निकलकर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष, संगठन, समर्पण और जनविश्वास की मिसाल माना जाता है। बैकुंठपुर की धरती का यह बेटा आज भाजपा के उन भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता है, जिन्होंने जमीन से उठकर सत्ता के शीर्ष तक अपनी पहचान बनाई।

साधारण परिवार से असाधारण सफर

साल 1971 में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के डुमरिया गांव में जन्मे मिथिलेश तिवारी का बचपन अभावों में बीता। परिवार आर्थिक रूप से बेहद मजबूत नहीं था, लेकिन संस्कार और मेहनत की पूंजी भरपूर थी। पिता देव नारायण तिवारी सरकारी सेवा में थे और बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहते थे।

घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि मिथिलेश तिवारी ने पढ़ाई के दौरान खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा पूरी की। संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने कभी हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर

पटना में पढ़ाई के दौरान वे छात्र राजनीति से जुड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अइश्ढ) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (फ़्र) की विचारधारा ने उनके राजनीतिक जीवन को दिशा दी।

उनकी भाषण शैली, संगठन क्षमता और कार्यकताओं के बीच मजबूत पकड़ ने जल्द ही उन्हें भाजपा के सक्रिय नेताओं की कतार में ला खड़ा किया।

युवा मोर्चा से लेकर भाजपा संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों तक उन्होंने लगातार मेहनत की। संगठन के प्रति निष्ठा और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।

हार से नहीं टूटा हौसला

राजनीति में सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। 2005 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। करीब एक दशक तक टिकट और राजनीतिक अवसरों का इंतजार किया, लेकिन जनता के बीच सक्रिय रहे।

इसी दौरान बैकुंठपुर में एक नारा बेहद लोकप्रिय हुआ —

जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है।

यह नारा सिर्फ चुनावी लाइन नहीं था, बल्कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और सामाजिक स्वीकार्यता का प्रतीक बन गया।

2015 में बदली राजनीतिक तस्वीर

साल 2015 का विधानसभा चुनाव मिथिलेश तिवारी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने महागठबंधन के मजबूत समीकरणों को चुनौती देते हुए जीत दर्ज की और पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे।

इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाजपा संगठन में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती गई। प्रधानमंत्री ठंशेल्लरिं टङ्क्ष की सभाओं के संचालन से लेकर संगठनात्मक रणनीति तक, वे पार्टी के भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए।

क्रिकेट राजनीति में भी दमदार हस्तक्षेप

मिथिलेश तिवारी सिर्फ विधानसभा की राजनीति तक सीमित नहीं रहे। बिहार क्रिकेट की राजनीति में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

बिहार क्रिकेट को पहचान दिलाने और पुराने विवादों के खिलाफ आवाज उठाने में उनकी भूमिका चर्चा में रही।

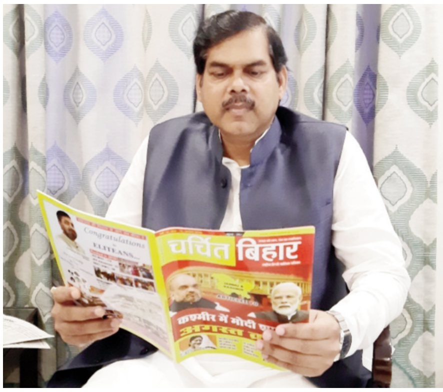

जनता से सीधा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत

मिथिलेश तिवारी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी, जिनकी भाषा में गांव की मिट्टी की खुशबू है। वे मंच से भाषण देते हैं तो कार्यकर्ता खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।

उनका राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक वैचारिक शैली और सहज व्यवहार का मिश्रण माना जाता है। यही कारण है कि संगठन और जनता— दोनों के बीच उनकी मजबूत पकड़ बनी हुई है।

शिक्षा मंत्री बनने के बाद बढ़ी जिम्मेदारी

अब बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके राजनीतिक कद में और वृद्धि हुई है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की कमान संभालना न सिर्फ उनके अनुभव पर भरोसे का संकेत है, बल्कि भाजपा नेतृत्व की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। बिहार के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे अब बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं।ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले मिथिलेश तिवारी को लोग ऐसे नेता के रूप में देखते हैं, जो जमीन की समस्याओं को समझते हैं और संघर्ष की कीमत जानते हैं।

संघर्ष की कहानी से प्रेरणा

गोपालगंज के एक छोटे से गांव से निकलकर बिहार की सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की यह कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है।

यह कहानी बताती है कि राजनीति में सिर्फ परिवार या विरासत ही सबकुछ नहीं होतीङ्ग मेहनत, संगठन और जनता का भरोसा भी इतिहास लिख सकता है।

संघर्ष जिनकी पहचान हो,
जनता जिनकी ताकत हो,
और संगठन जिनका परिवार हो
वही नेता राजनीति में स्थायी पहचान बनाते हैं।

राजपूत राजनीति और आरजेडी

अनूप नारायण सिंह

बिहार की राजनीति में राजपूत समाज हमेशा से एक निर्णायक सामाजिक-राजनीतिक शक्ति रहा है। आज जब विभिन्न दल राजपूत मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि किन राजनीतिक शक्तियों ने वास्तव में इस समाज को प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया है।

आजादी के बाद कांग्रेस की पारंपरिक द्विज राजनीति में राजपूत समाज को उसकी जनसंख्या और राजनीतिक योगदान के अनुरूप नेतृत्व नहीं मिला। यही कारण था कि 1960 के दशक से बड़ी संख्या में राजपूत समाज सोशलिस्ट धारा की ओर आकर्षित हुआ। बाद में उसने पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को भी स्वीकार किया। 1977 में मुख्यमंत्री पद के लिए कपूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह के बीच संघर्ष हुआ तो जनता पार्टी के 33 राजपूत विधायकों में से 17 ने अपनी जाति के नेता की बजाय कपूरी ठाकुर का समर्थन किया। यह इस बात का प्रमाण था कि बिहार का राजपूत समाज केवल जातीय राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक साझेदारी की राजनीति में भी विश्वास करता रहा है।इसी राजनीतिक प्रवाह का सबसे मजबूत रूप लालू प्रसाद यादव के दौर में दिखाई देता है। लालू यादव के राजनीतिक उभार में राजपूत समाज के एक बड़े वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोनपुर से उनकी पहली जीत हो या मधेपुरा से लोकसभा चुनाव, राजपूत समाज का समर्थन हमेशा उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। कहा जाता है कि सोनपुर चुनाव में सिताब दियारा के बाबू सत्यदेव सिंह ने खुलकर उनका साथ दिया था। वहीं मधेपुरा में भी राजपूत मतदाताओं ने कई बार निर्णायक भूमिका निभाई।लालू प्रसाद यादव ने भी इस विश्वास का सम्मान किया। लालू-राबड़ी शासनकाल में राजपूत समाज को सत्ता और संगठन दोनों में उल्लेखनीय भागीदारी मिली। जगदानंद सिंह, विजय कृष्ण, अशोक सिंह, हेमराज सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। रघुवंश बाबू को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख भूमिका दिलाई गई और 2004 में केंद्र की यूपीए सरकार बनने पर उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय भी मिला।2009 के लोकसभा चुनाव में जब आरजेडी महज चार सीटों पर सिमट गई थी, तब उन चार सांसदों में तीन राजपूत समाज से थे। रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह और उमा शंकर सिंह की जीत ने यह साबित किया कि आरजेडी और राजपूत समाज का रिश्ता केवल चुनावी नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास का रिश्ता था। उसी दौर में लालू प्रसाद यादव ने संसद में कहा था कि "हम भले चार सांसद हैं, लेकिन एक अहीर और तीन राजपूत मिलकर भी सरकार को चुनौती देने की ताकत रखते हैं।"रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने सारण के मढ़ौरा में रेल व्हील फैक्ट्री की स्थापना कराई। इस परियोजना में बड़ी मात्रा में स्थानीय किसानों, विशेषकर राजपूत परिवारों की भूमि अधिग्रहित हुई। इसके बदले मिले मुआवजे और रोजगार के अवसरों ने इलाके की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाया।हाल के वर्षों में भी आरजेडी ने राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व देने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। जगदानंद सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना इसका बड़ा उदाहरण था। वर्तमान में आरजेडी के चार लोकसभा सांसदों में बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2026 के विधान परिषद चुनाव में आरजेडी कोटे से केवल एक सीट उपलब्ध थी। ऐसी स्थिति में पार्टी के पास अनेक विकल्प थे, लेकिन उसने राजपूत समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता डॉ. सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद भेजकर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। सीमित अवसर होने के बावजूद राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व देना इस बात का संकेत था कि आरजेडी आज भी इस समाज को अपने राजनीतिक परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। इसका सकारात्मक असर बिहार के राजपूत मतदाताओं के बीच देखने को मिला और एक बार फिर यह चर्चा तेज हुई कि कौन सा दल वास्तव में उनके राजनीतिक हितों और भागीदारी की चिंता करता है।निस्संदेह, समय के साथ कुछ विवाद और तनाव भी पैदा हुए। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में यादव-राजपूत संबंधों में जो खटास आई, उसके पीछे स्थानीय नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं और क्षेत्रीय राजनीतिक संघर्ष भी जिम्मेदार रहे। लेकिन इन घटनाओं के आधार पर पूरे राजनीतिक संबंध को परिभाषित नहीं किया जा सकता।आज बिहार में "सवर्ण एकता" का नारा भी दिया जाता है, लेकिन राजपूत समाज के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उसकी राजनीतिक ताकत हमेशा सामाजिक गठबंधन, भागीदारी और व्यापक स्वीकार्यता से बनी है, न कि केवल सवर्ण ध्रुवीकरण से। बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राजपूत समाज ने सत्ता के पीछे चलने की बजाय सत्ता निर्माण में भूमिका निभाई है।यही कारण है कि बिहार की राजनीति में आरजेडी और राजपूत समाज के संबंधों पर चर्चा आज भी प्रासंगिक है। इतिहास, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक सम्मान के आधार पर यह संबंध केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

मंटू सिंह पटेल: मुखिया से मंत्री तक का संघर्ष शिक्षा और सकारात्मक राजनीति की मिसाल

सारण जिले के अमनौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रहे और बिहार सरकार के पूर्व आईटी मंत्री कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल बिहार की राजनीति में एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुए हैं, जिनकी पहचान केवल राजनीतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकार, शिक्षा के प्रति समर्पण और सकारात्मक राजनीति भी उनकी विशेष पहचान है।मुखिया से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले मंटू सिंह पटेल ने संघर्ष के बल पर विधायक और फिर मंत्री पद तक का सफर तय किया। बिना किसी राजनीतिक विरासत और गॉडफादर के उन्होंने बिहार की जटिल राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई। सारण की राजनीति में उन्होंने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मार्गदर्शन में राजनीति की बारीकियां सीखीं और वर्ष 2010 में नए परिसीमन के बाद बने अमनौर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए।वर्ष 2015 में जदयू-राजद गठबंधन के दौरान राजनीतिक परिस्थितियां उनके प्रतिकूल रहीं और भीतरघात के कारण उन्हें मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार को अपनी ताकत बनाया और लगातार जनता के बीच सक्रिय बने रहे।

यही सक्रियता और लोकप्रियता उन्हें वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में फिर से विजय के शिखर तक ले गई, जब भाजपा के टिकट पर उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की।मंटू सिंह पटेल की सबसे बड़ी पहचान उनके सामाजिक कार्य हैं। पूरे बिहार में पटेल छात्रावास निर्माण समिति के माध्यम से उन्होंने जिला स्तर पर छात्रावास निर्माण का अभियान चलाया, ताकि समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। उनका मानना है कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है।उनकी संवेदनशीलता का एक उदाहरण तब सामने आया, जब उन्होंने शहीद रामफल मंडल के परिजनों के लिए अपने विधायक मद और वेतन से पक्का मकान बनवाया।

यह कार्य बताता है कि उनके लिए राजनीति केवल सत्ता नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम है।अमनौर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास को नई गति दी। लगभग हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने और सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा आज भी क्षेत्र में होती है।बिहार की कुर्मी राजनीति में भी पिछले कुछ वर्षों में उनका कद तेजी से बढ़ा है। पटना के मिलर स्कूल मैदान में आयोजित कुर्मी एकता रैली की सफलता ने उन्हें राज्य स्तर पर एक प्रभावशाली कुर्मी नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी संगठन क्षमता और जनाधार को देखते हुए उन्हें बिहार सरकार में आईटी मंत्री बनने का अवसर मिला।राजनीति में रिश्तों और मयार्दाओं को निभाने वाले मंटू सिंह पटेल की सबसे बड़ी विशेषता उनकी उपलब्धता है। समर्थक हों या आम लोग, वे हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। यही कारण है कि उनके विरोधी भी उन्हें सकारात्मक राजनीति करने वाला जननेता मानते हैं।आज बिहार की राजनीति में मंटू सिंह पटेल एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं, जिन्होंने संघर्ष, सेवा और संगठन के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका राजनीतिक सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के जनसेवा के माध्यम से राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं

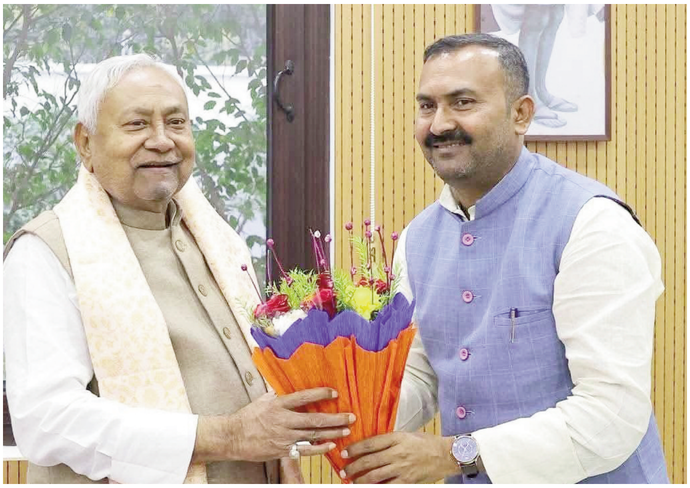

खत्म नहीं होगा आरक्षण, लेकिन... जेन-जी के सवाल पर संघ प्रमुख ने कोटा सिस्टम पर कर दी बड़ी अपील

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार (06 अगस्त) को दो टूक कहा कि देश में आरक्षण जारी रहेगा. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन लोगों को कोटा सिस्टम यानी आरक्षण प्रणाली से लाभ मिल चुका है, उन्हें दूसरों को भी वही मौके मिलने देना चाहिए और खुद ही आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिए. उन्होंने आरक्षण को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब तक सामाजिक भेदभाव है, तब तक आरक्षण जारी रहेगा.

भागवत ने मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 'जेन जी और 'जेन अल्फा' पर केंद्रित एक कार्यक्रम में 2,000 युवाओं को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं. इस कार्यक्रम के दौरान, फ़र प्रमुख ने हाल ही में हुए छात्र विरोध-प्रदर्शनों के बाद भारत के युवाओं की चिंताओं का जवाब देने की कोशिश की. जब उनसे आरक्षण के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जब तक सामाजिक भेदभाव मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए. लेकिन जिन लोगों को पहले ही फायदा मिल चुका है और जिनकी स्थिति बेहतर हो गई है, उन्हें दूसरों को भी वही मौके मिलने देने पर विचार करना चाहिए." बीकेसी के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में जेन-जी और जेन-अल्फा के साथ संवाद करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार में खामियां थी, तभी तो आंदोलन हुआ और आंदोलन तब होता है, जब बातचीत नाकाम हो जाती है. अगर सरकार ने पहले ही बात कर लेती, तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती. आंदोलन भी बातचीत का एक तरीका है. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जेन-जी और जेन-अल्फा पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है. उनकी बात हमें सुननी चाहिए. उनसे बातचीत में कमी थी, इसलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ. नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में प्रदर्शनों के बाद आरएसएस प्रमुख का युवाओं के साथ सबसे यह संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था. जंतर-मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा. गुरुवार को इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी आईआईएमयूएन के 15वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में भागवत ने युवाओं के सवालों का जवाब दिया. भागवत ने कहा कि हम लोग जब जेन-जी की उम्र में थे, तब बड़े बुजुर्ग जो कहते थे. हम मान लेते थे. उस पर सवाल नहीं करते थे. परंतु आज की जेन-जी सवाल करती है. उन्हें जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए. संघ प्रमुख ने आगे कहा कि मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि जेन-जी को आंदोलन नहीं करना चाहिए. संविधान ने हमें आंदोलन करने, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन कैसे करना है, यह देखना बहुत जरूरी है. दूसरी बात, आंदोलन हमारे या आपके खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए होना चाहिए. आंदोलन कोई एंटी-नेशनल नहीं है. जंतर-मंतर पर जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वे भी तो हमारे ही है. हमें उनकी बात और उनकी भावना को समझना चाहिए. आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ पर यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका कारण जानना होगा. हमें तय करना होगा कि कहां गड़बड़ी हुई. मैंने अखबार में ही पढ़ा कि आंदोलन में कुछ उपद्रवी शामिल हुए थे. भागवत ने विश्वास के साथ कहा कि अगर मुझे आंख मूंदकर भरोसा करना है, तो मैं जेन-जी पर कर सकता हूं. संघ प्रमुख भागवत ने शिक्षा व्यवस्था पर कहा कि शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है. वह सर्वसुलभ हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए. हमें भी सहयोग करना होगा. तभी सुधार होगा. बाद में पाठ्यक्रम की बात आनी चाहिए.

महिलाओं की भागीदारी के बारे में सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यह तय है कि उन्हें आगे आना चाहिए. उन्हें समान अधिकार मिलें, उन्हें बराबरी का हक मिले. सेम-सेक्स मैरिज पर पर भागवत ने कहा कि यह सब चल रहे सिस्टम को छोड़ देना चाहिए, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी. अगर आप नया सिस्टम ला रहे हैं, तो पहले सोसाइटी को उसके लिए तैयार करना होगा. उन्होंने कहा, "मैं आपको सीधे जवाब नहीं दूंगा. मैं आपसे कहूंगा कि आप देखें कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर आरक्षण के बारे में क्या सोचते थे. अगर हम ईमानदारी से उनकी सलाह मानें, तो कोई समस्या नहीं है." उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक कारणों से है. जब तक सामाजिक भेदभाव रहेगा, आरक्षण जारी रहेगा. जिन्हें यह मिला है और जिनकी हालत बेहतर हुई है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अब इसकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "अब बड़े पैमाने पर हमने इसका लाभ उठाया है, हमारी स्थिति अब ठीक है, इसलिए इसे दूसरों को दें. कुछ राज्यों में वर्गीकरण की मांग उठी है, और उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में इसका ज़िक्र किया है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह सभी को मिलना चाहिए. आरक्षण पाने वालों में एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि यह हमारी उन्नति के लिए है. यह कोई स्थायी उपाय नहीं है. हमें इसका फायदा उठाना है, खुद को बेहतर बनाना है और इसे उन लोगों के लिए उपयोगी बनाना है जिन्हें यह अभी तक नहीं मिला है." भागवत ने आगे कहा कि अगर सिस्टम को ठीक से लागू किया जाए, तो आरक्षण से जुड़ी कई चिंताओं का असरदार ढंग से समाधान किया जा सकता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. इस दौरान भागवत ने सोशल मीडिया के प्रभाव का भी उल्लेख किया और कहा कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब समाज उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करे. उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रभाव रखने वाले लोगों से जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि उनके कारण उनके अनुयायी को गलत दिशा में नहीं जाने चाहिए. उन्होंने फर्जी वीडियो और झूठी जानकारियों के बढ़ते खतरे का उल्लेख करते हुए लोगों से अपील की कि किसी भी सामग्री पर विश्वास करने से पहले उसकी विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करें. मोहन भागवत ने कहा कि सोशल मीडिया के उपयोग में आत्म-अनुशासन जरूरी है, क्योंकि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्याएं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि वे दूसरे रास्तों से फैलने लगती हैं. संघ प्रमुख ने कहा, "कभी-कभी टकराव खत्म होने के बाद हमें वहीं से आगे बढ़ना होता है जहां हमने छोड़ा था. इसलिए, हमेशा नफरत और दुश्मनी बनाए रखना समाधान नहीं है. जब कोई परेशानी आती है, तो हमें उसे संभालना होता है और उसे संभालने का एक तरीका भी होता है. हमें उस तरीके को अपनाना चाहिए."

क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा बदल देगा भारतीय राजनीति की दिशा?

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ राजनीति केवल चुनावी मंचों पर नहीं होती। संसद, सड़क, न्यायपालिका, मीडिया, विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन और अब सोशल मीडिया, ये सभी लोकतांत्रिक विमर्श के महत्वपूर्ण मंच बन चुके हैं। जब किसी मुद्दे पर इन विभिन्न मंचों का दबाव एक साथ दिखाई देता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हो जाता है।

धर्मेंद्र प्रधान प्रकरण ने भी यही संकेत दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या अब भारतीय राजनीति में जनता का संगठित दबाव फिर से निर्णायक भूमिका निभाने लगा है? या यह केवल एक विशेष परिस्थिति थी, जिसका प्रभाव समय के साथ सीमित हो जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर केवल वर्तमान घटनाओं में नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में भी छिपा है।

भारत में कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन, मंडल आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलनों तक अनेक उदाहरण बताते हैं कि जब जनता किसी मुद्दे पर व्यापक रूप से एकजुट होती है, तो सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। हालाँकि हर आंदोलन सत्ता परिवर्तन का कारण नहीं बना। कई आंदोलनों ने केवल नीतिगत बदलाव कराए, जबकि कुछ ने राजनीतिक दलों के उदय या पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए किसी भी आंदोलन का प्रभाव उसकी व्यापकता, नेतृत्व, संगठन और दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करता है।

धर्मेंद्र प्रधान प्रकरण को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। यदि यह केवल एक घटना बनकर रह जाता है, तो इसका प्रभाव सीमित होगा। लेकिन यदि विपक्ष इसे व्यापक जनभावनाओं से जोड़ने में सफल होता है, तो यह एक बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारतीय राजनीति में चुनावी अभियानों का केंद्र डिजिटल माध्यम और नेतृत्व आधारित प्रचार बन गया है। लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया कि सड़क पर उतरने वाले आंदोलनों की प्रासंगिकता अब भी समाप्त नहीं हुई है। जब छात्र, युवा, सामाजिक संगठन और विभिन्न समूह किसी मुद्दे पर एक साथ सक्रिय होते हैं, तो सरकार के सामने केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक चुनौती भी खड़ी होती है। लोकतंत्र में सरकारें केवल बहुमत से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से भी चलती हैं। इसलिए जनदबाव को पूरी तरह अनदेखा करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता। यही कारण है कि विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

भारतीय संसद लोकतांत्रिक जवाबदेही का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। किसी भी सरकार के निर्णयों की समीक्षा, प्रश्नों के उत्तर, बहस और आलोचना, ये सभी संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। धर्मेंद्र प्रधान प्रकरण में विपक्ष ने संसद के भीतर लगातार सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई। विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे केवल एक विभागीय मामला न मानकर व्यापक जवाबदेही का विषय बनाया। संसद में उठे प्रश्नों और बाहर चल रहे आंदोलनों के बीच एक प्रकार का समन्वय दिखाई दिया। राजनीतिक दृष्टि से यह विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव माना जा सकता है। पहले कई मुद्दों पर विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई देता था, लेकिन इस बार उसने अपेक्षाकृत अधिक समन्वित रुख अपनाने की कोशिश की।

भारतीय लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। शिक्षाविद, पूर्व प्रशासक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र संगठन, वकील, लेखक और विभिन्न पेशेवर समूह समय-समय पर सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया ने नागरिक समाज की आवाज को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब किसी भी मुद्दे पर विशेषज्ञों और आम नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रकरण में भी नागरिक समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विवाद न रहने देकर सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया।

कांग्रेस लंबे समय से ऐसे मुद्दे की तलाश में थी जो उसे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव बनाने का अवसर दे सके। यदि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को "जनदबाव की सफलता" के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह भविष्य में इसी मॉडल को अन्य मुद्दों पर भी अपनाने का प्रयास कर सकता है। इस रणनीति के मुख्य तत्व हो सकते हैं जनता के बीच लगातार अभियान। संसद में संयुक्त विपक्ष का समन्वित प्रदर्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार। छात्र, युवा और नागरिक संगठनों से संवाद। स्थानीय आंदोलनों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ना। लेकिन इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विपक्ष केवल विरोध तक सीमित रहता है या जनता के सामने ठोस वैकल्पिक नीतियाँ भी प्रस्तुत करता है।

अब राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश है। 2027 का विधानसभा चुनाव केवल राज्य की सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि उसे 2029 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। यहाँ की सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, धार्मिक विविधता, ग्रामीण-शहरी संतुलन और विशाल मतदाता आधार राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि विपक्ष किसी राष्ट्रीय मुद्दे को उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्रश्नों रोजगार, शिक्षा, कृषि, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जोड़ने में सफल होता है, तो चुनावी मुकाबला अधिक रोचक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस राज्य में अपना सबसे मजबूत संगठन रखती है। बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ता, मजबूत चुनावी मशीनरी और लंबे समय से विकसित राजनीतिक नेटवर्क उसे स्वाभाविक बढ़त प्रदान करते हैं।

डेहरी डालमियानगर ईओ की निर्ममतापूर्वक हत्या

आईजी वैभव पर उंगली उठाते हीं तेजस्वी हो रहे ट्रोल

अखिलेश कुमार

डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की निर्ममता पूर्वक की गई हत्या ने अधिकारियों की सुरक्षा के साथ हीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। घटना पिछले 1 अगस्त की है। रोहतास जिले के डेहरी डालमियानगर नगर परिषद के ईओ शहर में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने ड्राइवर के साथ रात करीब साढ़े आठ बजे पटना के लिए निकले थे। लेकिन एक घंटे बाद ही खबर मिली कि उनकी हत्या कर दी गई। यह खबर आग की तरह फैली और पुरे पुलिस प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया। घटना औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारुन थाना अंतर्गत सोन नहर के किनारे धनौती पुल के समीप घटित हुई थी। वहां से क्षत-विक्षत ईओ विमल कुमार को नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमुहार लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र, एसपी रौशन कुमार सहित औरंगाबाद के एसपी और अन्य पदाधिकारी रात में हीं ड्राइवर मिथिलेश कुमार को लेकर घटना स्थल गये। पुछताछ के दौरान ड्राइवर बार-बार बयान बदलने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुद हत्या करने की बात कहते हुए घटनाक्रम को विस्तार से बताया। ड्राइवर के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रड भी बरामद कर ली गई। इसके बाद गया जी जोन के आईजी विकास वैभव ने पुरे घटनाक्रम की जानकारी मिडिया से साझा की।

इसी बीच मृतिका की पत्नी बबीता देवी ने इस कांड में डेहरी विधायक की संलिप्तता की संभावना व्यक्त किया। उसने मिडिया से कहा कि डेहरी के कोई 'विधायक जी' रोज रोज फोन किया करते थे और उनके फोन आने पर मेरे पति तनाव में आ जाते थे। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।

वहीं दूसरी तरफ बिहार अर्बन सर्विस एसोसिएशन के बैनर तले राज्य के सभी ईओ अपनी, मृतक ईओ के आश्रितों को मुआवजा तथा नौकरी एवं हत्या में शामिल अपराधी को फांसी देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके बाद नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ हुई बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर आश्वासन मिलने पर 6 अगस्त को हड़ताल खत्म हुआ।

इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मृतक के पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप को डेहरी से निर्वाचित लोजपा आर विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह से जोड़कर उन्हें इनकाउंटर करने तक मांग कर दी!

साथ हीं गया जोन के आईजी विकास वैभव के कार्यशैली पर भी उंगली उठाते हुए उन्हें विधायक को बचाने का आरोप लगाया। इसके बाद तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रोल होने लगे। कारण कि ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने अपने स्विकरोक्ति बयान में जो बात बताई वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साबित कर दिया। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि मौत गोली लगने या धारदार हथियार के हमले से नहीं बल्कि मल्टिपल हार्ड एन्ड ब्लंट इंजरी यानी भारी और कठोर वस्तु से गंभीर चोट के कारण हुई है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी द्वारा दर्ज. प्राथमिकी में कहीं भी ड्राइवर मिथिलेश के अलावा न तो स्थानीय विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह का नाम है और ना हीं किसी अन्य का। ऐसे पुलिस ने हत्या में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है जिसमें पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के साथ हीं औरंगाबाद तथा रोहतास के पुलिस पदाधिकारियों की टीम शामिल है। अब देखना यह है कि इसमें और किन किन लोगो कु संलिप्तता उजागर होती है।

भाजपा की दरियादिली से उपेंद्र के दीपक में 'प्रकाश'

राजकिशोर सिंह

बिहार की राजनीति में कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक संदेश भी देते हैं. भाजपा विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार का इस्तीफा भी ऐसा ही कदम माना जा रहा है. इस इस्तीफे का उद्देश्य मंत्री दीपक प्रकाश के लिए बिहार विधान परिषद की सीट खाली करना है, तो यह केवल एक सीट का त्याग नहीं, बल्कि सरकार की संवैधानिक चुनौती का राजनीतिक समाधान हुए हैं. इस मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से जुड़ी है, जिसमें अदालत ने बिहार सरकार से पूछा कि यदि कोई मंत्री संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनता, तो वह मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है. अदालत ने सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा था. अब दीपक प्रकाश राज्यपाल के मनोनयन कोटे से विधान परिषद के सदस्य बनाए गए हैं और उनका शपथ ग्रहण भी हो गया है.

इसी संदर्भ में देवेश कुमार का इस्तीफा कई रणनीतिक संकेत छोड़कर राजनीतिक हलकों में सोंचने विचारने पर मजबूर कर दिया है. बिहार की सम्राट सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दीपक प्रकाश जल्द से जल्द विधान परिषद के सदस्य बन जाएं और उनके मंत्री पद पर कोई संवैधानिक प्रश्नचिह्न न खड़ा रह पाये. यह फैसला बताता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सरकार ने गंभीरता से लिया है. अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद सरकार के पास संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के अलावा बहुत अधिक विकल्प नहीं बचे थे. इसलिए उक्त कदम उठाए गए हैं. भाजपा संगठन के भीतर भी यह संदेश गया है कि संगठन और सरकार के व्यापक हित में व्यक्तिगत पद का त्याग किया जा सकता है. यदि देवेश कुमार ने वास्तव में इसी उद्देश्य से इस्तीफा दिया है, तो इसे पार्टी अनुशासन और नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास के उदाहरण के रूप में भी सदा देखा जाएगा. भाजपा नीत गठबंधन की राजनीति और उसका पालन कैसे किया जाए उसके लिए देवेश कुमार का उदाहरण वर्तमान से लेकर भविष्य का प्रस्तुत किया जाएगा. हालांकि विपक्ष इस घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख सकता है. विपक्ष यह तर्क दे सकता है कि यदि समय रहते संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाती, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती. वहीं सरकार यह कहेगी कि उसने संविधान के दायरे में रहकर स्थिति का समाधान निकाल लिया है.

बहरहाल, यह घटनाक्रम केवल एक एमएलसी के इस्तीफे की कहानी नहीं है. यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीति तीनों के बीच संतुलन का उदाहरण है. इससे यह संदेश भी जाता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के मामले में न्यायपालिका की टिप्पणियां केवल औपचारिक नहीं होतीं; उनका राजनीतिक और प्रशासनिक असर भी दिखाई देता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दीपक प्रकाश निर्धारित समय के भीतर विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, तो सरकार तत्काल संवैधानिक संकट से बाहर निकल आयी है. लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में राजनीति बहुमत के साथ-साथ संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी उतना ही आवश्यक है.

बिहार के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह बिहार विधान परिषद में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं. मगर इसके साथ क्लाउज है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171(5) के अनुसार राज्यपाल सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को ही मनोनीत कर सकते हैं, जिनकी साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो. मकसद यह था कि विधान परिषद में ऐसे विशेषज्ञों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जगह मिले जो चुनावी राजनीति के इतर (यानी उस दबाव से मुक्त होकर) अपने अनुभव के आधार कानून निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सके. संविधान में यह भी जिक्र है कि राजनीति या किसी राजनीतिक दल में योगदान को मनोनयन का आधार नहीं माना जायेगा. अगर कम शब्दों में समझें तो राजनेताओं से इतर समाज के बुद्धिजीवियों, कलाकारों को भी विधान परिषद में जगह देने की बात थी. शर्त यह भी रखी गई थी कि जिनका मनोनयन हो उसके आगे इनमें से किसी योग्यता का जिक्र हो.

रोलोमो अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा के मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश के मनोनयन को लेकर जारी गजट देखा है. उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि वे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं या समाज सेवी हैं. हालांकि समाज सेवी ऐसा टर्म है, जिसके भीतर कोई भी आ जाता है. आपने गरीबों में कभी कंबल बांट दिया तो हो गये समाज सेवी. मगर दीपक प्रकाश समाज सेवी हैं, यह भी नहीं कहा गया.

सच यह है कि मसला सिर्फ दीपक प्रकाश का नहीं है. बिहार विधान परिषद में इस वक्त उन्हें मिलाकर जो 12 सदस्य हैं, उनमें छह जदयू के हैं और अब तक छह भाजपा के थे, मगर अब दीपक प्रकाश अपनी पिता के पार्टी रालोमो के सदस्य हैं. इनमें अगर बहुत खींच तान कर निकाला जाये तो दो लोग मिलते हैं, जो संविधान की भावना के अनुरूप हैं. उनमें एक प्रो. (डॉ) रामवचन राय हैं, जो साहित्यकार हैं और दूसरे डॉ. राज्यवर्धन आजाद हैं, जो एक ख्याति प्राप्त आंखों के डॉक्टर हैं. डॉ. राज्यवर्धन आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद के पुत्र और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कृति आजाद के भाई हैं. शेष खांटी राजनेता है.

विधान परिषद में मनोनयन कोटे से वर्तमान में जदयू के अशोक चौधरी, जनक राम, राज्यवर्धन आजाद, डॉ राम वचन राय, संजय कुमार सिंह, ललन कुमार सर्राफ, प्रो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजय सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, घनश्याम ठाकुर, निवेदिता सिंह और नव मनोनयन के बाद शपथ ग्रहण करने वाले

पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश हैं. अब इनमें कोई इन दोनों के अलावा साहित्यकार, वैज्ञानिक हो तो मुझे नहीं मालूम है. मगर इतना समझ में आता है कि मनोनयन के मामले में राजनीतिक दलों ने मिलकर संविधान की भावना का कचरा कर दिया है. 12 सीटों को सत्ताधारी दलों ने अपने हिसाब से बांट लिया है और अपने लोगों को उपकृत करने का जरिया बना लिया है. इनमें भी ज्यादातर पोलिटिकल लोगों को भरा गया है. वैसे, यह स्थिति सिर्फ वर्तमान एनडीए सरकार की नहीं है. इसके पहले कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव एवं राबड़ी देवी के भी शासनकाल में होता रहा है. कमोबेश सभी राजनीतिक दलों के नुमाइंदे एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं.

हैरत की बात यह है कि इसी विधान परिषद में बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वतंत्रता सेनानी, बाबूलाल मधुकर जैसे मगही कवि और सियाराम तिवारी जैसे तबला वादक का मनोनयन हुआ था. मगर ये गिने चुने नाम हैं. इस कोटे का ज्यादातर इस्तेमाल सत्ताधारी दल ही करते आ रहे हैं. अगर ऐसा ही है तो क्यों न इस कोटे को खत्मकर दिया जाये और इसे भी चुनाव के जरिये भरा जाये? अगर नेता ही आयें तो चुन कर आयें. उन्हें मनोनयन की सुविधा क्यों मिले? यह सवाल वर्षो से राजनीतिक हलकों में चर्चा के केन्द्र में रहा है. पहले बिहार में वामपंथ की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी भाकपा (माले) विधान परिषद की अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर पुरजोर विरोध करती थी. लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में भाकपा (माले) की सियासी रणनीतिकारों ने सोंच में बदलाव लाकर इसमें भाग लेना मुनासिब समझा. आज भाकपा (माले) की शशि यादव बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं.

बहरहाल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भाजपा में विलय करने के दबावों के बीच सात महीने की बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि पार्टी के नेता और गठबंधन सरकार में पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश को 5 अगस्त को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया है. इसके चलते ही आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे. एमएलसी के तौर पर उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 में समाप्त हो जाएगा, उसी दौरान 12 सीटें रिक्त हो जाएंगी. इसके चलते भाजपा और उसके सहयोगी के बीच गहन वार्ता का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है. भाजपा नेता देवेश कुमार द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से सात महीने पहले अपने पद से इस्तीफा देने के बाद दीपक प्रकाश एमएलसी बने हैं.

दीपक प्रकाश ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल के बीच 22 दिनों का अंतराल था. लगभग छह महीने तक मंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि उनके पास किसी भी सदन में कोई सीट नहीं थी. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया था. अब जब रालोमो नेता दीपक प्रकाश बिहार के राज्यपाल कोटे से एमएलसी बन गए हैं, तो लगता यही है कि यह माना जा रहा है कि उन्हें 7 महीने की मोहलत मिल गई है.

उपेंद्र कुशवाहा के पास अपनी पत्नी स्नेहलता, या पार्टी के किसी अन्य नेता को मंत्री बनाने का मौका था लेकिन उन्होंने अपने गैर विधायक बेटे के लिए एक पद सुरक्षित करने पर जोर दिया. एक भाजपा नेता ने कहा, "एनडीए हाल ही में रिक्त हुई 10 सीटों में से आरएलएम को एक एमएलसी सीट दे सकता था, लेकिन भाजपा को उम्मीद थी कि उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी का हमारे साथ विलय कर लेंगे. इससे पहले भी पार्टी ने आरएलएम-भाजपा विलय की इसी उम्मीद के साथ कुशवाहा को राज्यसभा का कार्यकाल दिया था."

बिहार के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भाजपा उपेन्द्र कुशवाहा की मांगों को किस हद तक पूरा कर सकती है, इस मुद्दे पर पुनर्विचार करती नजर आ रही है. भाजपा नेता ने कहा, "अब जब भाजपा के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो कुशवाहा के एक प्रमुख नेता हैं, तो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को क्यों खुश करती रहे? सात महीने बाद आरएलएम प्रमुख को एक और कठिन चुनौती का सामना करना पड़ेगा." इस मुद्दे पर आरएलएम के ही नेता ने कहा, "फिलहाल हमने दीपक प्रकाश के लिए सात महीने का कार्यकाल स्वीकार कर लिया है क्योंकि तत्काल कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं था. लोग चाहे जितनी भी बातें करें कि भाजपा हम पर विलय का दबाव डाल रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई हैं.

राज्य में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम अनुच्छेद 164(4) के तहत संवैधानिक अनिवार्यता पर केंद्रित हैं, जिसके अनुसार किसी भी गैर-निर्वाचित व्यक्ति को मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद के लिए निर्वाचित या मनोनीत होना अनिवार्य है. दीपक प्रकाश जदयू के नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल में मंत्रिमंडल में हुए विभिन्न बदलावों के दौरान अपनी छह महीने की छूट अवधि की सीमा पार कर चुके हैं, जिसके चलते एक जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौती दी गई है.

बिहार मंत्रिमंडल से दीपक प्रकाश को हटाए जाने से बचाने के लिए भाजपा नेता देवेश कुमार ने पहले ही अपनी एमएलसी सीट छोड़ दी. इससे राज्यपाल द्वारा मनोनीत सीट खाली हो गई, जिससे चुनाव चक्र की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल नॉमिनेशन संभव हो पाए. आरएलएम ने फिलहाल एक सीट हासिल कर ली है, लेकिन हाल के घटनाक्रम बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेदों को उजागर करते हैं. बांकीपुर उपचुनाव की हार ने भाजपा हाईकमान को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट में हार की सबसे बड़ी वजह जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के नैरेटिव का जवाब नहीं दे पाना बताया गया है यानी किशोर के नैरेटिव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में विफल होना है. हालांकि, भाजपा ने साफ किया है कि वह इस हार को लेकर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी.

नीतीश कुमार....पेशेवर पॉलिटिशियन!

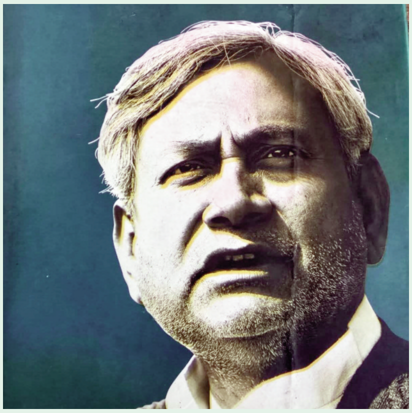

सौरभ कुमार। नीतीश कुमार जो अपनी राजनीतिक विद्वता से विरोधियों को परास्त कर देते थें,चुनावी गणित बैठाना नीतीश कुमार के लिए बच्चे का खेल था,अपने अद्भुत विचारधारा से किसी को भी सत्ता से बेदखल करने का हैसियत से परिपूर्ण,कॉटन और खादी के कुर्ता-पाजामा पर 40 साल की संसदीय जीवन को खपा देने वाले नीतीश कुमार अपनी मजी से दूसरे दलों के नेताओं को मंत्री बनाने का ताकत रखते थें,नीतीश कुमार समय-समय पर सभी से लड़ें,क्या कांग्रेस-क्या बीजेपी,लालू यादव हों या शरद यादव,रामविलास पासवान,कभी तेजस्वी यादव तो कभी चिराग पासवान,बारी-बारी प्रतिद्वंदी दोस्त बनते गयें और दोस्त प्रतिद्वंदी भी बनें,हिन्दू-मुस्लिम की राजनीति को जेब में रखकर,पिछड़ा को अतिपिछड़ा और दलित को महादलित बनाने का करतब सिर्फ नीतीश कुमार के पास था,अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई को नजरअंदाज करते हुए आधी-आबादी(महिलाओं) की लड़ाई को समझा और महिलाओं का एक वोटबैंक तैयार कर दिया,आरक्षण की राजनीति का परवाह किये बिना नीतीश कुमार ने स्कूलों के बच्चों के लिए समान स्तर के कई योजना लाए,नीतीश कुमार कब किस पर अपना हाथ रख दें उनके हाथ को भी पता नहीं,कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने किसी का कर्ज.नहीं रखा,न सेवा करने वाले का और न ही सुरक्षा में लगे जवान का,जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थें तो उस वक्त 30 साल पहले दिल्ली में अपने एक ढरड से वादा किया था कि उसके घर(हरियाणा) उसके बच्चों की शादी में जरूर आएंगे,नीतीश कुमार ने नवंबर 2024 में उस ढरड के घर हरियाणा पहुंचकर यह वादा भी पूरा किया था,नीतीश कुमार 2020 में 46 सीट जीतकर भी देश के सबसे ताकतवर नेताओं की सूची में खड़े थें लेकिन 2025 में 85 सीट जीतकर भी नीतीश कुमार देश के सबसे कमजोर नेताओं की सूची में शामिल हो गयें,नीतीश कुमार अंततः प्रकृति से हार गयें,नीतीश कुमार आगे स्वस्थ रहें यही कामना हैं!

बिना पद के भी सियासत और समाज में चर्चा का चेहरा हैं मसरख के युवराज सुधीर सिंह

मसरख। राजनीति में किसी व्यक्ति की ताकत अक्सर उसके पद से तय होती है, लेकिन सारण की सियासत में मसरख के युवराज सुधीर सिंह एक ऐसा नाम हैं, जिनके पास आज न विधायक का पद है, न सांसद का, न मुखिया, सरपंच या जिला परिषद सदस्य की कुर्सी और न ही किसी राजनीतिक दल का कोई संगठनात्मक पद, बावजूद इसके सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक उनकी चर्चा लगातार बनी रहती है। पिछले वर्ष पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह के निधन के बाद सुधीर सिंह के व्यक्तित्व और कार्यशैली में एक अलग तरह की परिपक्वता भी दिखाई देने लगी है। अब वह हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जरूरी मुद्दों पर ही बोलते हैं और बेवजह की बहस से खुद को दूर रखते हैं। पिता के जाने के बाद जैसे जिम्मेदारियों ने उन्हें भीतर से और गंभीर कर दिया हो।2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तरैया विधानसभा क्षेत्र से लोजपा का टिकट सुधीर सिंह के नाम पर लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन चुनाव के अंतिम दौर में राजनीतिक समीकरण बदले और टिकट की तस्वीर भी बदल गई। चुनावी मैदान में प्रत्याशी नहीं बन पाने के बावजूद तरैया से उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। तरैया उनकी कर्मभूमि रही है और विधायक नहीं रहते हुए भी वह लगातार क्षेत्र के लोगों के सुख-दुख में भागीदार बने हुए हैं। किसी परिवार में बीमारी हो, आर्थिक परेशानी हो, किसी जरूरतमंद को तत्काल सहायता चाहिए हो या कोई सामाजिक संकट सामने आया हो, सुधीर सिंह अपनी क्षमता के अनुसार मदद के लिए आगे आते रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में उनकी सक्रियता को केवल चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाता।उनकी सामाजिक सक्रियता का दायरा तरैया और सारण तक भी सीमित नहीं है। बिहार के किसी हिस्से में बड़ी मानवीय या सामाजिक घटना सामने आती है तो सुधीर सिंह वहां भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। मधुबनी नरसंहार का मामला हो, छपरा में बच्ची से जुड़ी घटना हो या भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला, पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनका दर्द सुनने और अपनी ओर से मदद करने की कोशिश उनकी कार्यशैली का हिस्सा रही है। वह उन लोगों में हैं जो राजनीति को सिर्फ मंच, भाषण और चुनाव तक सीमित नहीं मानते, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी के घर पहुंचकर उसके आंसू पोंछने को भी राजनीति और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा समझते हैं।सुधीर सिंह की पहचान स्वाभाविक रूप से एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी जुड़ी है। वह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं और उनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ सिंह का नाम सारण, चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सम्मान के साथ लिया जाता रहा है। बिहार की राजपूत राजनीति में इस परिवार की अपनी मजबूत जगह रही है। परिवार की राजनीतिक सक्रियता आज भी दिखाई देती है। उनके चचेरे भाई रणधीर सिंह मांझी से जदयू के विधायक हैं, जबकि उनके चाचा

केदारनाथ सिंह बनियापुर से भाजपा के विधायक हैं और पांचवीं बार विधानसभा पहुंचे हैं। इतनी मजबूत राजनीतिक विरासत के बीच सुधीर सिंह ने अभी तक अपनी पहचान किसी राजनीतिक पद के सहारे नहीं, बल्कि लोगों के बीच अपनी मौजूदगी और सामाजिक गतिविधियों के जरिए बनाने की कोशिश की है।राजनीति के साथ खेल और युवाओं से उनका जुड़ाव भी पुराना रहा है। मसरख में क्रिकेट टूर्नामेंटों के आयोजन के जरिए उन्होंने शुरूआती स्तर पर कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराया। ऐसे कई खिलाड़ी आगे चलकर बड़े स्तर तक पहुंचे और आईपीएल तथा भारतीय क्रिकेट से जुड़े। मुकेश कुमार से लेकर साकिबुल गनी तक के नाम इस सिलसिले में लिए जाते हैं। मसरख जैसे क्षेत्र में क्रिकेट के जरिए युवाओं को अवसर देने की कोशिश भी सुधीर सिंह की सामाजिक सक्रियता का एक अलग पक्ष है।सोशल मीडिया पर भी सुधीर सिंह की अपनी अलग पहचान है। उनके पोस्ट अक्सर वायरल होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर वह समय-समय पर लाइव आकर अपनी बात रखते हैं। उनकी बेबाकी के कारण समर्थकों के साथ विरोधियों की नजर भी उन पर रहती है और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी गतिविधियों से पीछे हटते नजर नहीं आते। दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया पर राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता है, उसी व्यक्ति के बारे में यह भी चर्चा है कि विरोधी

खेमे का कोई जरूरतमंद व्यक्ति मदद के लिए पहुंच जाए तो वह केवल राजनीतिक पहचान देखकर दरवाजा बंद नहीं करते।दिखावा सुधीर सिंह की कार्यशैली का हिस्सा नहीं माना जाता। वह जितना सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, उतना ही जमीनी स्तर पर भी लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उनके समर्थक उनकी राजनीति को ह्यदिल की राजनीतिह्न कहते हैं। वह फैसले दिमाग से कम और दिल से ज्यादा लेते हैं और शायद यही उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। यही भावुकता कई बार उन्हें विवादों में भी ले आती है, लेकिन सामाजिक मामलों में पीछे हट जाना उनकी आदत नहीं बनी है।पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग को लेकर शुरू हुए बड़े आंदोलन में भी सुधीर सिंह की सक्रिय भूमिका सामने आई है और वह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए एक बार फिर वह अपने परिवार की राजनीतिक विरासत से जुड़े मुद्दे को लेकर सड़क और सोशल मीडिया दोनों जगह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।सुधीर सिंह के सामने फिलहाल कोई राजनीतिक पद नहीं है और न ही यह तय है कि आने वाले समय में वह किस राजनीतिक दल या किस चुनावी भूमिका में नजर आएंगे। 2025 में तरैया का टिकट अंतिम समय में हाथ से निकल जाना भी उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।\

लेकिन इसके बावजूद तरैया और मसरख की जमीन पर उनकी सक्रियता कम नहीं हुई। शायद यही वजह है कि आज उनकी चर्चा सिर्फ इस सवाल पर नहीं होती कि वह किस पद पर हैं, बल्कि इस सवाल पर होती है कि जब किसी जरूरतमंद को मदद की जरूरत होती है तो वह किसके पास जाता है। राजनीति की औपचारिक कुर्सियों से दूर रहते हुए भी लोगों के सुख-दुख में लगातार मौजूद रहना ही फिलहाल सुधीर सिंह की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बनती जा रही है।

उपचुनाव - भाजपा के लिए क्या चेतावनी की घंटी बज चुकी है?

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव केवल सरकार बनाने या सीटें जीतने का माध्यम नहीं होते हैं, बल्कि वे जनता की नब्ज को समझने का सबसे विश्वसनीय पैमाना भी हैं। विशेषकर उपचुनावों को अक्सर "मूड इंडिकेटर" माना जाता है। इन चुनावों में मतदाता किसी सरकार को हटाने या बनाने के बजाय उसके कामकाज, संगठन की स्थिति, नेतृत्व की स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। हाल के उपचुनावों के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत छोड़े हैं। जिन तीन राज्यों में उपचुनाव हुए, उनमें से दो राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक चर्चा बिहार की उस सीट की हो रही है, जिसे भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन की परंपरागत राजनीतिक पहचान से जुड़ी रही है। इस सीट पर मिली हार ने राजनीतिक गलियारों में अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्वाभाविक रूप से चुनावी हार और जीत का विश्लेषण इतना आसान नहीं होता कि एक-दो कारणों में पूरी कहानी समेट दी जाए। प्रत्येक चुनाव स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवारों की छवि, संगठन की सक्रियता, जातीय-सामाजिक समीकरण, सत्ता विरोधी भावना, विकास कार्यों और चुनावी रणनीति जैसे अनेक कारकों का परिणाम होता है। फिर भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए भविष्य में भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि इन उपचुनावों के नतीजों को केवल सीटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि उपचुनाव का असर आम चुनाव जैसा नहीं होता है। यह बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी देने वाले संकेतक साबित होते हैं। उपचुनाव कई बार यह बताते हैं कि जनता सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट है, संगठन कितना सक्रिय है और स्थानीय स्तर पर नेताओं की पकड़ कितनी मजबूत बनी हुई है। इतिहास गवाह है कि अनेक बार उपचुनावों के परिणामों ने भविष्य के बड़े चुनावों की दिशा भी तय की है। कई राजनीतिक दलों ने उपचुनाव में मिले झटकों के बाद अपनी रणनीति बदली और अगले चुनावों में शानदार वापसी की। वहीं कई दल ऐसे भी रहे जिन्होंने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया और बाद में उन्हें बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। इसी दृष्टि से वर्तमान उपचुनावों को भी देखा जा रहा है।

तीन राज्यों में हुए उपचुनावों में दो राज्यों में हार का सामना करना किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए चिंता का विषय माना जाएगा। भाजपा आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसका संगठन देश के लगभग प्रत्येक राज्य में सक्रिय है। इसलिए उससे अपेक्षाएँ भी अधिक रहती हैं। यदि किसी राज्य में हार होती है तो उसे स्थानीय परिस्थिति कहा जा सकता है। लेकिन जब अलग-अलग राज्यों में समान प्रकार के संकेत मिलने लगें तो पार्टी नेतृत्व के लिए आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है। इन चुनावों ने यह संकेत दिया है कि केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता हर चुनाव में जीत की गारंटी नहीं बन सकती। स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय संगठन और उम्मीदवार की स्वीकार्यता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। राजनीति में कुछ सीटें केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं होती है, बल्कि वे किसी दल की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाती है। बिहार की यह सीट भी लंबे समय से भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती रही है। यहां पार्टी का संगठन मजबूत माना जाता था और नेतृत्व का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता था। ऐसी स्थिति में यदि पार्टी को हार का सामना करना पड़े तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह हार केवल एक सीट की हार नहीं है, बल्कि संगठन की जमीनी स्थिति का संकेत भी हो सकती है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे भाजपा की लोकप्रियता समाप्त हो गई है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। भाजपा की सफलता के पीछे केवल उसका संगठन ही नहीं है, बल्कि वर्षों से विकसित सामाजिक गठबंधन भी रहा है। पिछले एक दशक में पार्टी ने विभिन्न जातीय और सामाजिक वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन हाल के समय में यह चर्चा बढ़ी है कि संगठनात्मक बदलावों के दौरान कुछ पुराने नेताओं और पारंपरिक सामाजिक समीकरणों की उपेक्षा हो रही है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षों से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता, तो उसका प्रभाव चुनाव में दिखाई देना स्वाभाविक है। राजनीतिक दल केवल शीर्ष नेतृत्व के भरोसे नहीं चलते। बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी और स्थानीय नेता ही चुनाव की वास्तविक ताकत होते हैं। हर राजनीतिक दल समय के साथ बदलाव करता है। नई पीढ़ी को अवसर देना आवश्यक है। नए चेहरों को आगे लाना भी लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन बदलाव का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि पुराने अनुभव को पूरी तरह किनारे कर दिया जाए। अनुभव और ऊर्जा का संतुलन ही किसी भी सफल संगठन की पहचान होता है। यदि अनुभवी नेताओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होगा।

राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी ताकत उनका आंतरिक संवाद होता है। जब कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक पहुँचती है तो संगठन मजबूत रहता है। लेकिन यदि कार्यकर्ताओं को लगे कि उनकी राय का महत्व कम हो गया है, तो धीरे-धीरे असंतोष बढ़ने लगता है। यह असंतोष हमेशा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता है। कई बार यही नाराजगी मतदान के दिन निष्क्रियता के रूप में सामने आती है। राजनीति में निष्क्रिय कार्यकर्ता कई बार सक्रिय विरोधी से भी

अधिक नुकसान पहुंचा देता है। हर चुनाव में उम्मीदवार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यदि उम्मीदवार जनता से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र में सक्रिय है और लोगों की समस्याओं को समझता है तो पार्टी को अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसके विपरीत यदि उम्मीदवार केवल संगठन की पसंद बनकर रह जाए और जनता से उसका संवाद कमजोर हो तो कठिनाई बढ़ जाती है। उपचुनावों में अक्सर उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि निर्णायक साबित होती है। विपक्ष की सक्रियता को भी समझना होगा किसी दल की हार केवल उसकी कमजोरी से नहीं होती। कई बार विपक्ष की रणनीति अधिक प्रभावी होती है। यदि विपक्ष स्थानीय मुद्दों को सही तरीके से उठाए, सामाजिक समीकरणों को साधे और मतदाताओं तक लगातार पहुंचे तो उसे लाभ मिल सकता है। इसलिए भाजपा के लिए यह जरूरी होगा कि वह केवल अपनी कमियों का ही नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति का भी गंभीर अध्ययन करे।

राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अंततः स्थानीय समस्याओं पर भी निर्भर करता है। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, अस्पताल, शिक्षा, नगर विकास, यातायात और स्थानीय प्रशासन जैसे मुद्दे मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। यदि जनता को लगे कि उसकी स्थानीय समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो उसका असर मतदान पर पड़ सकता है। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी संपत्ति उसका कार्यकर्ता होता है। नेता चुनाव के समय दिखाई देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता पूरे पांच वर्ष जनता के बीच रहता है। यदि कार्यकर्ता उत्साहित रहेगा तो चुनावी अभियान स्वतः मजबूत होगा। यदि वही निराश हो जाए तो सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी। इसीलिए सफल राजनीतिक दल समय-समय पर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखते हैं। कई बार छोटी हार भविष्य की बड़ी जीत का रास्ता भी खोलती है। यदि राजनीतिक दल अपनी कमियों को स्वीकार कर समय रहते सुधार कर लें तो जनता उन्हें दूसरा अवसर भी देती है। भारतीय राजनीति में इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। इसलिए इन उपचुनावों को भाजपा के लिए केवल हार नहीं बल्कि आत्ममंथन का अवसर भी माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में जिस तरह अपना विस्तार किया है, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। अनेक राज्यों में सरकारें बनाना, लगातार चुनावी सफलताएँ हासिल करना और मजबूत संगठन खड़ा करना पार्टी की बड़ी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन राजनीति का एक अटल सिद्धांत है कि कोई भी दल लगातार सफलता के भरोसे नहीं चल सकता है। समय-समय पर जनता ऐसे संकेत देती है, जिन्हें समझना और स्वीकार करना आवश्यक होता है। हालिया उपचुनावों के परिणाम भी ऐसे ही संकेतों के रूप में देखे जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए लगातार जीत प्रेरणा का स्रोत होती है। लेकिन यही लगातार सफलता यदि आत्मसंतोष में बदल जाए तो चुनौती पैदा हो सकती है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि कई दल चुनाव इसलिए नहीं हारे क्योंकि जनता ने उन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने यह मान लिया कि जनता

हमेशा उनके साथ रहेगी। उपचुनावों के संदर्भ में भी यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या संगठन का एक हिस्सा यह मान बैठा था कि पारंपरिक सीटों पर जीत स्वतः मिल जाएगी? यदि ऐसा हुआ है तो यह सोच भविष्य में और बड़ी चुनौती बन सकती है। हर राजनीतिक दल की यात्रा में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिन्होंने वर्षों तक संगठन को खड़ा किया होता है। उन्होंने कठिन समय में पार्टी का विस्तार किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और सामाजिक विश्वास अर्जित किया। समय के साथ नेतृत्व बदलना स्वाभाविक है। नई पीढ़ी को अवसर मिलना भी जरूरी है। लेकिन जब परिवर्तन के दौरान पुराने नेताओं की भूमिका अचानक सीमित हो जाती है या उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है, तो उसका प्रभाव केवल उन नेताओं तक सीमित नहीं रहता है। उनके साथ वर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं में भी यह संदेश जाता है कि संगठन अब उनकी भूमिका को पहले जैसा महत्व नहीं देता। यह भावना चुनाव के दौरान सक्रियता को प्रभावित कर सकती है। भाजपा की चुनावी सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार उसका व्यापक सामाजिक गठबंधन रहा है। पार्टी ने समय के साथ विभिन्न वर्गों, समुदायों और सामाजिक समूहों में अपना विस्तार किया। लेकिन सामाजिक गठबंधन स्थायी नहीं होते हैं। उन्हें लगातार संवाद, प्रतिनिधित्व और विश्वास के माध्यम से बनाए रखना पड़ता है। यदि किसी समूह को यह महसूस होने लगे कि उसकी भागीदारी कम हो रही है या उसकी आवाज पहले जैसी नहीं सुनी जा रही, तो वह धीरे-धीरे दूरी बना सकता है। यह दूरी हमेशा विरोध के रूप में नहीं दिखती, कई बार मतदान प्रतिशत या चुनावी उत्साह में कमी के रूप में सामने आती है। आधुनिक चुनावों में डिजिटल प्रचार, बड़े जनसभाएँ और सोशल मीडिया महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई बूथ पर ही जीती या हारी जाती है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता मतदाता सूची की जानकारी रखता है, स्थानीय समस्याओं को समझता है और चुनाव के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में अहम भूमिका निभाता है। यदि बूथ स्तर का संगठन कमजोर पड़े या कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो जाए, तो उसका असर परिणामों पर पड़ सकता है। यही कारण है कि सफल राजनीतिक दल चुनाव समाप्त होने के बाद भी बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाए रखते हैं। भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रभाव महत्वपूर्ण है, लेकिन विधानसभा उपचुनावों में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका अक्सर अधिक निर्णायक होती है। मतदाता यह भी देखते हैं कि उनका स्थानीय विधायक या उम्मीदवार उनके बीच कितना उपलब्ध रहता है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उसकी सक्रियता कैसी है। जनता से उसका संवाद कितना मजबूत है। यदि स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ता है, तो राष्ट्रीय लोकप्रियता भी हर बार उसकी भरपाई नहीं कर पाती है। हर चुनाव से पहले सबसे अधिक असंतोष टिकट वितरण को लेकर सामने आता है। यदि लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाए, तो कई बार संगठन के भीतर असहमति पैदा होती है। दूसरी ओर यदि केवल पुराने समीकरणों के आधार पर निर्णय लिए जाएँ, तो नई पीढ़ी निराश हो सकती है। इसलिए टिकट वितरण केवल राजनीतिक गणित नहीं, बल्कि संगठनात्मक संतुलन की परीक्षा भी होता है।

किसी भी चुनाव में केवल अपनी ताकत पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता। विपक्ष की तैयारी, उम्मीदवार, प्रचार और स्थानीय गठबंधन भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। यदि विपक्ष किसी क्षेत्र में एकजुट हो जाए, स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाए और मतदाताओं के बीच निरंतर सक्रिय रहे, तो मुकाबला कठिन हो सकता है। इसलिए किसी भी हार का विश्लेषण केवल अपनी कमियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज का मतदाता, विशेषकर युवा, पहले की तुलना में अधिक जागरूक और अपेक्षाकृत स्वतंत्र निर्णय लेने वाला माना जाता है। वह केवल राजनीतिक पहचान के आधार पर मतदान नहीं करता, बल्कि रोजगार, शिक्षा, अवसर, डिजिटल सुविधाओं और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को भी महत्व देता है। इस वर्ग के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना किसी भी दल के लिए आवश्यक है। हाल के वर्षों में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है। कई राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों के बराबर या उससे अधिक रहा है। इसलिए चुनावी रणनीति में महिलाओं की अपेक्षाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से शामिल करना आवश्यक हो गया है। हर चुनाव के बाद राजनीतिक दल समीक्षा करते हैं। लेकिन प्रभावी समीक्षा वही होती है जिसमें केवल जीत का उत्सव या हार का दोषारोपण न हो, बल्कि तथ्यों के आधार पर कमियों की पहचान की जाए। यदि संगठन कार्यकर्ताओं की बात सुने, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करे, सामाजिक संवाद बढ़ाए और उम्मीदवार चयन में संतुलन बनाए रखे, तो किसी भी झटके से उबरना संभव है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ दलों ने छोटी चुनावी हार से सीख लेकर बाद के बड़े चुनावों में उल्लेखनीय वापसी की है। उपचुनावों ने यह स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। जनता समय-समय पर अपने निर्णय से राजनीतिक दलों को संकेत देती रहती है। तीन राज्यों में हुए उपचुनावों में दो राज्यों में मिली हार और बिहार में महत्वपूर्ण सीट पर आया परिणाम भाजपा के लिए आत्ममंथन का अवसर हो सकता है। वहीं विपक्ष के लिए यह उत्साह का विषय अवश्य है, लेकिन उसे भी इसे अंतिम राजनीतिक निष्कर्ष नहीं मानना चाहिए। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि अंतिम निर्णय हमेशा जनता के हाथ में होता है। जो दल जनता की अपेक्षाओं, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और कार्यकर्ताओं के सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखता है, वही लंबे समय तक राजनीतिक रूप से सफल रहता है।

दुनिया के प्रमुख जेन-जी आंदोलन - बदलता भारत जागरूक युवा और लोकतंत्र की नई दिशा

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों के अनुरूप समाज और राजनीति को नई दिशा देने का प्रयास करती है। स्वतंत्रता संग्राम की पीढ़ी ने आजादी का सपना साकार किया, उसके बाद की पीढ़ियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और आर्थिक विकास की नींव रखने में योगदान दिया। अब दुनिया जिस पीढ़ी की ओर सबसे अधिक उम्मीद से देख रही है, वह है जेनरेशन-जेड। लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं की यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक संपर्क के युग में पली-बढ़ी है। इनके सोचने, संवाद करने और अपनी बात रखने के तरीके पहले की पीढ़ियों से काफी अलग हैं। दुनिया के अनेक देशों में बीते कुछ वर्षों के दौरान जेन-जी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन देखने को मिले। इन आंदोलनों ने शिक्षा, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय और सरकारी नीतियों जैसे विषयों को वैश्विक बहस का हिस्सा बनाया। कई स्थानों पर इन आंदोलनों ने सरकारों को अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया, तो कई जगह आंदोलन हिंसा, आगजनी, पुलिस कार्रवाई और व्यापक सामाजिक तनाव में भी बदल गए।

भारत भी इस वैश्विक परिवर्तन से अछूता नहीं है। यहां भी युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पारदर्शिता की मांग ने लाखों युवाओं को एक साझा मंच पर ला खड़ा किया। लेकिन भारत के कुछ आंदोलनों ने एक अलग उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जहां विरोध के साथ अनुशासन, रचनात्मकता और लोकतांत्रिक मयार्दा को बनाए रखने का प्रयास दिखाई दिया। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन इसी संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे।

भारत विश्व का सबसे युवा देशों में से एक है। देश की बड़ी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह जनसांख्यिकीय स्थिति भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाएं, समय पर रोजगार और समान अवसर मिले तो यही शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला बन सकती है। लेकिन जब युवाओं को लगे कि उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं या भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक लंबित रहती हैं, तब असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। लोकतंत्र में इस असंतोष को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करना नागरिकों का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। आज का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता है, बल्कि वह पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसर की भी मांग करता है। वह सरकारों से यह अपेक्षा करता है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू हों और प्रतिभा के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाए।

भारत भी इस वैश्विक परिवर्तन से अछूता नहीं है। यहां भी युवाओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पारदर्शिता की मांग ने लाखों युवाओं को एक साझा मंच पर ला खड़ा किया। लेकिन भारत के कुछ आंदोलनों ने एक अलग उदाहरण भी प्रस्तुत किया, जहां विरोध के साथ अनुशासन, रचनात्मकता और लोकतांत्रिक मयार्दा को बनाए रखने का प्रयास दिखाई दिया। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन इसी संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे।

जेन-जी को अक्सर "डिजिटल नेटिव" कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है जिसने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपने जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना है। सूचना तक तत्काल पहुंच ने इनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है। आज किसी भी घटना की जानकारी कुछ ही मिनटों में देश-दुनिया तक पहुंच जाती है। छात्र संगठन, सामाजिक समूह और नागरिक मंच सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से एक-दूसरे से जुड़ते हैं। यही कारण है कि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी, प्रश्नपत्र लीक या भर्ती में अनियमितता की खबर कुछ ही समय में राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाती है। हालांकि डिजिटल माध्यम अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इनके साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अपुष्ट सूचनाएं, अफवाहें और भ्रामक सामग्री कभी-कभी तनाव बढ़ा सकती हैं। इसलिए डिजिटल साक्षरता और तथ्य आधारित संवाद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत में हर वर्ष करोड़ों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इनमें केंद्रीय और राज्य स्तरीय सेवाओं, बैंकिंग, रेलवे, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सरकारी नौकरियों से संबंधित परीक्षाएं शामिल होती हैं। इन परीक्षाओं के साथ लाखों परिवारों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अनेक अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि किसी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो जाए या परीक्षा रद्द करनी पड़े तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों को होता है। पेपर लीक केवल परीक्षा की समस्या नहीं है, यह सामाजिक विश्वास, प्रशासनिक

क्षमता और न्याय की भावना से भी जुड़ा विषय है। यही कारण है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार आज राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है।

किसी भी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना केवल कानूनी अपराध नहीं है। यह लाखों मेहनती छात्रों के आत्मविश्वास और भरोसे को प्रभावित करता है। जब किसी परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, तब छात्रों का समय, धन और मानसिक ऊर्जा तीनों प्रभावित होते हैं। पेपर लीक के दुष्परिणाम कई स्तरों पर दिखाई देते हैं- योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की भावना। सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दबाव। समाज में भ्रष्टाचार के प्रति निराशा का वातावरण। इसलिए परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है।

पिछले कुछ समय में सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहल तकनीक आधारित परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में की गई है। सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के लिए विशेषज्ञों का एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित किया है। इस समिति का उद्देश्य ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने के सुझाव देना है जिससे प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, डेटा संरक्षण और परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यबल में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, पूर्व

किसी भी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होना केवल कानूनी अपराध नहीं है। यह लाखों मेहनती छात्रों के आत्मविश्वास और भरोसे को प्रभावित करता है। जब किसी परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, तब छात्रों का समय, धन और मानसिक ऊर्जा तीनों प्रभावित होते हैं। पेपर लीक के दुष्परिणाम कई स्तरों पर दिखाई देते हैं- योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की भावना। सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। छात्रों पर मानसिक और आर्थिक दबाव।

आईबी निदेशक तपन डेका तथा आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी जैसे अनुभवी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। इन विशेषज्ञों का अनुभव तकनीकी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कठोर कानूनी प्रावधान तथा त्वरित न्यायिक प्रक्रिया की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो और ईमानदार अभ्यर्थियों का विश्वास बना रहे।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नागरिक सरकार की नीतियों से असहमति व्यक्त कर सकते हैं। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जब आंदोलन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा फैलाने या सामान्य जनजीवन को बाधित करने लगते हैं, तब उनका मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि आंदोलन शांतिपूर्ण, अनुशासित और रचनात्मक तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो वे समाज में व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। भारत में हाल के कुछ छात्र आंदोलनों ने इसी दिशा में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जहां विरोध के साथ स्वच्छता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक अनुशासन पर भी बल दिया गया।

भारत में परीक्षा सुधार केवल तकनीकी बदलाव का विषय नहीं है। यह युवाओं के विश्वास, प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई तकनीक, कठोर कानून और संस्थागत सुधार किस प्रकार परीक्षा प्रणाली को अधिक

विश्वसनीय बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर देशभर में गंभीर चर्चा हुई है। कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं के मन में चिंता पैदा की। वर्षों की मेहनत के बाद जब किसी परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, तब केवल एक परीक्षा नहीं टलती, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के सपने, योजनाएं और भविष्य की समय-सीमा भी प्रभावित होती है।

पेपर लीक किसी एक राज्य या किसी एक परीक्षा तक सीमित समस्या नहीं रही। समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र समय से पहले बाहर आने या संगठित गिरोहों द्वारा परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे कई कारण माने जाते हैं- प्रश्नपत्रों के मुद्रण और वितरण की पारंपरिक व्यवस्था में सुरक्षा संबंधी कमजोरियां। परीक्षा संचालन में शामिल विभिन्न स्तरों पर मानवीय हस्तक्षेप। संगठित आपराधिक गिरोहों की सक्रियता। डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और मिलीभगत। इन कारणों से स्पष्ट हुआ कि केवल प्रशासनिक सतर्कता पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीक के अनुरूप पुनर्गठित करना आवश्यक है।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के बाद दुनिया भर में युवाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक संपर्क ने युवाओं को स्थानीय मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय विमर्श से जोड़ने का अवसर दिया। परिणामस्वरूप अनेक देशों में जेन-जी के नेतृत्व वाले आंदोलन सामने आए। इन आंदोलनों के उद्देश्य अलग-अलग थे, लेकिन उनमें एक समानता थी- युवाओं ने अपने भविष्य, अधिकारों और अवसरों को लेकर खुलकर आवाज उठाई। हालांकि इन आंदोलनों का स्वरूप एक जैसा नहीं रहा। कहीं वे शांतिपूर्ण रहे, तो कहीं हिंसा, आगजनी और पुलिस कार्रवाई के कारण व्यापक विवाद का विषय बने। भारत में परीक्षा प्रणाली और युवाओं से जुड़े आंदोलनों को समझने के लिए इन अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का अध्ययन उपयोगी है।

वर्ष 2023 में फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पेंशन सुधार नीति के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव का श्रमिक संगठनों और युवाओं ने विरोध किया। इसी वर्ष 17 वर्षीय नाहेल की पुलिस गोलीबारी में मृत्यु के बाद स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए। घटनाओं के दौरान हजारों वाहनों में आग लगा दी गई। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। दुकानों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दिनों तक झड़पें होती रही। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इन घटनाओं ने यह प्रश्न खड़ा किया कि लोकतांत्रिक विरोध और हिंसा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।

2019 में चिली की राजधानी सैंटियागो में मेट्रो किराए में मामूली वृद्धि की घोषणा हुई। शुरूआत में छात्रों ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे-धीरे यह

वर्ष 2023 में फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पेंशन सुधार नीति के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव का श्रमिक संगठनों और युवाओं ने विरोध किया। इसी वर्ष 17 वर्षीय नाहेल की पुलिस गोलीबारी में मृत्यु के बाद स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए।

आंदोलन आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय और सरकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक जनआंदोलन में बदल गया। प्रदर्शनों के दौरान अनेक मेट्रो स्टेशनों को आग लगा दी गई। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। हिंसा और झड़पों में कई लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल जैसी स्थिति बनी। यह आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि यदि समय रहते संवाद स्थापित न हो, तो सीमित मुद्दा भी व्यापक सामाजिक असंतोष का रूप ले सकता है।

2019 में हांगकांग में प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध में छात्रों और युवाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया। शुरूआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन समय के साथ स्थिति जटिल होती गई। कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। पेट्रोल बम फेंके गए। सार्वजनिक परिवहन बाधित हुआ। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन ने दुनिया का ध्यान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन की ओर आकर्षित किया।

2024 में गाजा युद्ध के संदर्भ में अमेरिका के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, जैसे हार्वर्ड, कोलंबिया और यूसीएलए में छात्रों ने प्रदर्शन किए। इन आंदोलनों की विशेषता यह रही कि अधिकांश स्थानों पर छात्रों ने शांतिपूर्ण धरना, चर्चा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। हालांकि कुछ परिसरों में पुलिस हस्तक्षेप हुआ। प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। गिरफ्तारियां हुईं। प्रशासन और छात्रों के बीच तनाव बढ़ा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक देशों में भी विश्वविद्यालय परिसर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए हैं।

2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के विरोध में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। प्रारंभिक विरोध धीरे-धीरे व्यापक राजनीतिक संकट का रूप लेने लगा। कई शहरों में आगजनी हुई। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष हुए। सैकड़ों लोगों की मृत्यु की खबरें सामने आईं। इंटरनेट सेवाएं कई दिनों तक बाधित रही। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि यदि असंतोष और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के बीच संतुलन न बने, तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है।

2024झ25 के दौरान नेपाल के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर छात्रों ने कई चरणों में प्रदर्शन किए। अधिकांश प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन कुछ स्थानों पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुई। पथराव की घटनाएं सामने आई। बल प्रयोग करना पड़ा। नेपाल का अनुभव बताता है कि लगातार संवाद और संस्थागत सुधार से अधिकांश आंदोलनों को शांतिपूर्ण दिशा दी जा सकती है।

2022 में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ईंधन, खाद्यान्न और दवाओं की कमी ने आम नागरिकों का जीवन प्रभावित कर दिया। बड़ी संख्या में युवाओं ने 'अरगलया' आंदोलन में भाग लिया। शुरूआत में आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बाद के चरण में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया। कुछ सरकारी परिसरों पर कब्जा किया गया। कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। यह आंदोलन बताता है कि लंबे आर्थिक संकट सामाजिक असंतोष को किस प्रकार व्यापक राजनीतिक आंदोलन में बदल सकते हैं।

जर्मनी में जेन-जी ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास जैसे मुद्दों पर व्यापक अभियान चलाए। इन आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएं थी शांतिपूर्ण मार्च। जनजागरूकता अभियान। विद्यालय और विश्वविद्यालय आधारित कार्यक्रम। नीति-निमार्ताओं से संवाद। हालांकि कुछ अवसरों पर सड़क जाम और पुलिस के साथ सीमित तनाव भी देखने को मिला।

ब्रिटेन में भी युवाओं ने जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अनेक प्रदर्शन किए। अधिकांश कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहे। कुछ अवसरों पर सड़क अवरोध। यातायात प्रभावित होना। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटाना जैसी घटनाएं सामने आई। फिर भी अधिकांश आंदोलनों में संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई।

इन सभी उदाहरणों का अध्ययन कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने लाता है, आज का युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक, तकनीकी रूप से सक्षम और संगठित है। उसकी अपेक्षाएं केवल रोजगार तक सीमित नहीं हैं; वह पारदर्शिता, समान अवसर और जवाबदेही भी चाहता है। जहां सरकारों ने समय रहते संवाद किया, वहां तनाव अपेक्षाकृत कम रहा। जहां संवाद कमजोर पड़ा, वहां कई आंदोलन हिंसक दिशा में बढ़ गए। जब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है या हिंसा होती है, तब मूल मुद्दे की बजाय कानून-व्यवस्था चर्चा का केंद्र बन

दुनिया के जेन-जी आंदोलनों से यह स्पष्ट होता है कि आज की युवा पीढ़ी अपने अधिकारों, भविष्य और लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग है। लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उसकी मांगों पर नहीं, बल्कि उसके तरीकों पर भी निर्भर करती है। जहां संवाद, अनुशासन और लोकतांत्रिक मयार्दा बनी रही, वहां आंदोलनों ने अधिक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। वहीं, जहां हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, वहां मूल मुद्दे कई बार पीछे छूट गए।

यूजीसी बिल और बुलडोजर की राजनीति ने बदला क्या बिहार का चुनावी समीकरण ?

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

राजनीति केवल घोषणाओं और नारों से नहीं चलती, बल्कि जनता की धारणा, विश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी चुनावी परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। किसी भी सरकार का निर्णय यदि समाज के किसी वर्ग में असंतोष या असुरक्षा की भावना पैदा करता है, तो उसका प्रभाव केवल उस वर्ग तक सीमित नहीं रहता बल्कि व्यापक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में दो ऐसे मुद्दे प्रमुखता से चर्चा में रहे हैं। पहला- यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित विधायी बदलावों को लेकर उठी बहस और दूसरा- बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बनने वाली राजनीतिक धारणा। इन दोनों विषयों ने अलग-अलग सामाजिक वर्गों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। एक ओर कुछ सवर्ण संगठनों और बुद्धिजीवियों ने यूजीसी बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं, वहीं दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई की राष्ट्रीय बहस ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच आशंकाओं को जन्म दिया।

यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित बदलावों पर देशभर में विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई। कुछ शिक्षाविदों, छात्र संगठनों तथा सामाजिक समूहों ने इसका समर्थन किया तो कुछ ने विरोध भी किया। विरोध करने वाले कुछ वर्गों का मानना था कि प्रस्तावित बदलावों से अवसरो की समानता और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर असर पड़ सकता है। इसी दौरान कुछ सवर्ण संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि नीति निर्माण में उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार को सभी वर्गों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए था ताकि किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना पैदा न हो। हालांकि सरकार की ओर से ऐसे आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके प्रति लोगों के विश्वास का निर्माण भी उतना ही आवश्यक माना जाता है।

लोकतंत्र में कई बार वास्तविकता से अधिक प्रभाव धारणा का होता है। यदि किसी समुदाय को यह महसूस होने लगे कि उसकी चिंताओं को नहीं सुना जा रहा है, तो वह भावना चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल लगातार संवाद, जनसंपर्क और विश्वास निर्माण पर जोर देते हैं। कई बार छोटे-छोटे मुद्दे भी बड़े चुनावी विमर्श का हिस्सा बन जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में अवैध निमार्णों और अपराध के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय रही है। इन कार्रवाइयों के समर्थकों का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि ऐसी कार्रवाई हमेशा विधिक प्रक्रिया, न्यायालय के आदेशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार होना चाहिए। इसी बहस के बीच कई राजनीतिक दलों ने बुलडोजर कार्रवाई को चुनावी मुद्दा भी बनाया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी राज्य में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा बढ़ती है, तो मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में आशंका की भावना उत्पन्न हो सकती है कि ऐसी कार्रवाई उनके विरुद्ध अधिक हो सकती है। दूसरी ओर, इस धारणा से सभी मुस्लिम मतदाता सहमत हो, ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी समुदाय के भीतर राजनीतिक मत विविध होते हैं।

बिहार के संदर्भ में भी कुछ विश्लेषकों ने यह तर्क रखा कि यदि उत्तर प्रदेश जैसी कठोर कार्रवाई का राजनीतिक संदेश यहां भी जाता है, तो उसका असर मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर पड़ सकता है। हालांकि इस प्रकार के दावों की पुष्टि व्यापक सर्वेक्षणों और चुनावी अध्ययनों से ही की जा सकती है। बिहार की राजनीति में अक्सर यह कहा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के दौरान कानून-व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को लेकर एक अलग राजनीतिक छवि बनी। उनके समर्थक मानते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास उनकी राजनीति की विशेषता रहा है। दूसरी ओर, उनके आलोचक अन्य मुद्दों पर सवाल उठाते रहे हैं। इसलिए किसी एक समुदाय की भावनाओं को पूरे राजनीतिक परिदृश्य का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं होगा। बिहार की राजनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों से गहराई से प्रभावित रही है। यहां विकास, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और स्थानीय नेतृत्व जैसे अनेक मुद्दे मतदान के निर्णय को प्रभावित करते हैं। यदि किसी समय सवर्ण वर्ग के एक हिस्से में नाराजगी दिखाई देती है और दूसरी ओर मुस्लिम मतदाताओं के बीच आशंका का वातावरण बनता है, तो राजनीतिक दल इन दोनों वर्गों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

लोकतांत्रिक राजनीति में किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल उसके कानूनी पहलुओं से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव और जनविश्वास से भी किया जाता है। यूजीसी बिल को लेकर उठे सवाल हो या बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बनी राजनीतिक बहस, दोनों ने अलग-अलग वर्गों में अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। हालांकि यह कहना कि किसी एक कारण से पूरे चुनावी परिणाम प्रभावित हो गए, पर्याप्त प्रमाण के बिना उचित नहीं होगा। चुनाव अनेक कारकों- स्थानीय उम्मीदवार, गठबंधन, विकास कार्य, सामाजिक समीकरण, नेतृत्व और मतदाताओं की प्राथमिकताओं, से मिलकर तय होते हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र में संवाद, पारदर्शिता और सभी समुदायों के बीच विश्वास बनाए रखना किसी भी सरकार और राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती और आवश्यकता है।

बिहार की राजनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों, जातीय संतुलन और समुदायों के बीच विश्वास की राजनीति पर आधारित रही है। यहां चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, नेतृत्व की स्वीकार्यता और भविष्य की उम्मीदों पर भी लड़े जाते हैं। यही कारण है कि जब किसी वर्ग में उपेक्षा की भावना या किसी समुदाय में असुरक्षा की धारणा पैदा होती है, तो उसका प्रभाव चुनावी माहौल पर दिखाई देने लगता है। किसी भी सरकार द्वारा लाया गया कानून या नीति तभी व्यापक समर्थन प्राप्त कर पाती है, जब उसके उद्देश्य और प्रभाव को समाज के विभिन्न वर्ग स्वीकार करें। यदि किसी वर्ग को यह महसूस हो कि उसकी बात नहीं सुनी गई या उसके हितों की अनदेखी हुई है, तो असंतोष जन्म ले सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए नीति निर्माण जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसके बारे में प्रभावी संवाद स्थापित करना होता है।

बांकीपुर उपचुनाव में
जन सुराज पार्टी
के तरफ से
श्री प्रशांत किशोर जी
को जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं
हार्दिक
शुभकामनाएं!
बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज की जीत जनता के विश्श्वास और बदलाव के संकल्प की जीत है।
जन सुराज के सभी कार्यकर्ता एवं समर्थकों की ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं!
चुनाव चिन्ह : स्कूली बैग
जन सुराज
JAN SURAJ
दानिश खान

बिना किसी पद के जनसेवा का संकल्प: बैकुंठपुर में बदलाव की नई उम्मीद बने विकास कुमार सिंह

अनूप नारायण सिंह

राजनीति में अक्सर यह धारणा बन जाती है कि जनसेवा केवल पद मिलने के बाद ही संभव है। लेकिन गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता विकास कुमार सिंह इस सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी या संगठनात्मक पद के वे लगातार क्षेत्र के युवाओं, किसानों और आम लोगों के बीच रहकर विकास की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं।

बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के बुधसी गांव के रहने वाले विकास कुमार सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की पीड़ा को स्वयं महसूस किया है। यही कारण है कि आज उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने से रोकना और उन्हें अपने ही क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है।

उनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है जब वहां का युवा शिक्षित, प्रशिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम हो। इसी सोच के साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षणों से जोड़कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

विकास कुमार सिंह केवल रोजगार की बात नहीं करते, बल्कि युवाओं को यह विश्वास भी दिलाते हैं कि यदि सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण मिले तो गांव में रहकर भी सम्मानजनक आजीविका अर्जित की जा सकती है। उनका प्रयास है कि पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क विकसित हो, जहां स्थानीय युवाओं को आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल सिखाया जा सके।

उनकी सोच केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। वे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर भी लगातार लोगों के बीच संवाद कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि विकास केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी से संभव होता है।

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विकास कुमार सिंह बिना किसी पद या अधिकार के भी हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, जरूरतमंदों की सहायता करने और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी के कारण उनकी पहचान एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में बन रही है, जो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं।

आज जब राजनीति में पद और प्रतिष्ठा की चर्चा अधिक होती है, ऐसे समय में विकास कुमार सिंह का प्रयास यह संदेश देता है कि यदि नीयत साफ हो और समाज के प्रति समर्पण हो, तो बिना किसी पद के भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा उनका "स्किल डेवलपमेंट से आत्मनिर्भरता" अभियान आने वाले समय में न केवल युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है, बल्कि पूरे क्षेत्र को विकास के एक नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

श्री साईं आदर्श नेत्रालय की अनूठी पहल जरुरतमंदों को मिल रही है आंखों की रौशनी

श्री साई अमर हीरा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की इकाई है श्री साई आदर्श नेत्रालय

श्री साईं आदर्श नेत्रालय में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लाभुक

राजेश पंजिकार (ब्यूरोचीफ)

बांका शहर मे कई वर्षो से संचालित श्री साई अमर हीरा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की एक इकाई श्री साई आदर्श नेत्रालय के द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है। इस नेत्रालय के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर लगाकर जरूरतमंदों के आंखों की जांच योग्य चिकित्सकों के द्वारा कराया जा रहा है. तथा जरूरतमंदों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन योग्य चिकित्सकों के द्वारा साई आदर्श नेत्रालय जो कटोरिया रोड बांका में अवस्थित है, में निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है. संस्था के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रभु महादेव की प्रेरणा से मुझे जन सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिसमें नियमित रूप से श्री साई आदर्श नेत्रालय के द्वारा योग्य चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस क्रम में मरीजों के ऑपरेशन के साथ-साथ दवाई, चश्मा, भोजन एवं रहने की सुविधा निःशुल्क रुप में प्रदान की जा रही है। श्री साई आदर्श नेत्रालय के द्वारा बांका में पिछले कई वर्षों से जिला स्वास्थ्य समिति एवं वीजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुंबई की संस्था के सौजन्य से निःसहाय एवं जरूरत मंद लगभग 10 हजार से अधिक मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन एवं लैंस प्रत्यारोपण किया गया है। लिहाजा श्री साई आदर्श नेत्रालय के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह ने जिला स्वास्थ्य समिति बांका एवं वीजन फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुंबई को श्री साई आदर्श नेत्रालय बांका को सहयोग प्रदान करने हेतु कोटि-कोटि आभार प्रकट करते है।

आंखों की जांच करते डॅक्टर

प्रभु महादेव की प्रेरणा से मुझे जनसेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साई आदर्श नेत्रालय के द्वारा जरूरतमंद लोगों का कई वर्षों से लगातार योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा मोतियाबिंद मरीजों का सफल ऑपरेशन की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

धर्मेंद्र कुमार सिंह
प्रबंध निर्देशक
श्री साई आदर्श नेत्रालय
कटोरिया रोड, बांका

Mount Litera Zee School : आधुनिक शिक्षा और संस्कार का उत्कृष्ट केंद्र

ज्ञान, तकनीक और संस्कार का संगम : Mount Litera Zee School

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ बांका

बांका। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। Mount Litera Zee School बांका में आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षकों और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के साथ विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने वाला एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। विद्यालय का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। कई तरह की सुविधाओ से युक्त यह स्कूल शंकरपुर स्थित बिसनपुर रोड बांका में अवस्थित है।

विश्वस्तरीय सुविधाएं -

स्मार्ट डिजिटल कक्षाएँ
247 सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था
रोबोटिक्स लैब
जीपीएस युक्त परिवहन सुविधा
स्विमिंग पूल
बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन एवं नेट क्रिकेट की सुविधा
इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
समृद्ध पुस्तकालय एवं रीडिंग जोन
आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ
संगीत एवं नृत्य कक्ष
आर्ट एवं क्राफ्ट स्टूडियो
वातानुकूलित ऑडिटोरियम
लिफ्ट सुविधा
सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ
वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता
क्विज प्रतियोगिताएँ
नाटक एवं रंगमंच
संगीत एवं गायन
नृत्य, कला एवं चित्रकला
योग एवं ध्यान
आत्मरक्षा प्रशिक्षण
स्काउट एवं गाइड
सामुदायिक सेवा
नेतृत्व विकास कार्यक्रम
करियर काउंसलिंग
ओलंपियाड की तैयारी
पब्लिक स्पीकिंग प्रशिक्षण
शैक्षणिक उत्कृष्टता
सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा

अनुभवी एवं योग्य शिक्षक
तकनीक आधारित आधुनिक शिक्षण प्रणाली
प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान
अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर
प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता

Mount Litera Zee School में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक तकनीक, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्यों के समन्वय से विद्यार्थियों को एक सफल, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है। यही कारण है कि यह विद्यालय अभिभावकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

"हमारा सपना है कि बांका में शिक्षा का ऐसा दीपक जले, जिसकी लौ पूरे देश में अपनी पहचान बनाए। Mount Litera Zee School केवल एक विद्यालय नहीं, बल्कि भविष्य के योग्य, संस्कारी और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करने का अभियान है।

-"ध्रुव कुमार सिंह
मैनेजिंग डायरेक्टर
Mount Litera Zee School, बांका

आगामी 12सितम्बर 2026 को लगने बाले लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक का हुआ आयोजन

प्रधान एवं जिल सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ बांका

बांका में आज दिनांक 5 अगस्त 2026 को श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका श्री सत्यभूषण आर्य के निदेर्शानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका के कक्ष में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय बांका में आयोजित किया जाना है, इस संबंध में ट्रैफिक चालान से जुड़े वादों के निष्पादन हेतु परिवहन विभाग के पदाधिकारीयों के साथ बैठक की गई, इस बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बांका श्रीमती सपना रानी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि परिवहन विभाग ट्रैफिक चालान से जुड़े जो भी सुलहनीय मामले हैं उसमें नोटिस जारी कर गाड़ी ऑनर्स को प्री लिटिगेशन हेतु लोक अदालत से पहले बुलाकर सुलह समझौते के आधार पर वाद का निष्पादन कराया जाय तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चालान से जुड़े वादों का निष्पादन हो इस हेतु नोटिस जारी किया जाए। इस बैठक में जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारी अउब्लड निशा राज, ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार तथा ट्रैफिक थाना प्रभारी प्रवीण कुमार झा उपस्थित रहे।

गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

समाजसेवी राहुल डोकानिया ने की बिशेष पहल

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ बांका

बांका में 27 जुलाई 2026 (सोमवार): गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर आज बांका जिला मुख्यालय में गौ भक्तों एवं सामाजिक कार्यकताओं ने उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ विशाल जनसमर्थन का प्रदर्शन किया। गौ सम्मान आान अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत सैकड़ों गौ भक्तों की उपस्थिति में 28,150 हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिलाधिकारी, बांका को सौंपा गया।

इस अवसर पर अभियान से जुड़े सभी कार्यकताओं ने गौ माता को भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा एवं राष्ट्र की आस्था का प्रतीक बताते हुए उन्हें राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने की मांग को प्रमुखता से रखा। उपस्थित जनसमूह ने इस जनआंदोलन को जन-जन तक पहुँचाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प भी लिया।

इस अभियान में के. आर. मिशन स्कूल, बांका के छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता फँछ' उङ्ख्'ल्त्रं (राहुल डोकानिया), सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रदीप सिंह, बमबम सिंह, आशुतोष रघुवंशी एवं ऋषि रजक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विशेष रूप से दिल्ली से पधारीं श्रीमती किरण झा ने इस जनआंदोलन को गति प्रदान करने हेतु अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई तथा अभियान को व्यापक जनसमर्थन दिलाने का आान किया।

अभियान से जुड़े वक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि देशभर से प्राप्त जनसमर्थन एवं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान करने की मांग पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। अंत में सभी गौ भक्तों, सहयोगी संस्थाओं, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते गौ सम्मान अभियान समिति के सदस्यगण

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का जिले के प्रभारी मंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने किया उद्घाटन

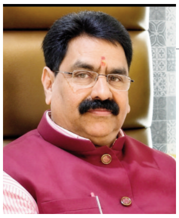

राजेश पंजिकार(ब्यूरो चीज)

:बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 का शुभारंभ 30 जुलाई को कटोरिया के अवरखखा में माननीय प्रभारी मंत्री-सह-राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार सरकार डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर शंखध्वनि के साथ विधिवत किया गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, बिहार सरकार श्री श्रवण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री श्री संजय कुमार सिंह तथा शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार श्री मिथिलेश कुमार तिवारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में माननीय विधायक, बाँका श्री रामनारायण मंडल, माननीय विधायक, अमरपुर श्री जयंत राज, माननीय विधायक, बेलहर श्री मनोज यादव, माननीय विधायक, कटोरिया श्री पूरनलाल टुडू, माननीय विधान पार्षद ,स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र, भागलपुर-सह-बाँका, श्री विजय कुमार सिंह की गरिमामय उपस्थिति तथा जिला पदाधिकारी, बाँका एवं पुलिस अधीक्षक, बाँका सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

उद्घाटन से पूर्व माननीय प्रभारी मंत्री-सह-राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार सरकार डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्थापित टेंट सिटी एवं जीविका दीदी की रसोई का लोकार्पण किया गया। इसके उपरांत उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित विभागीय प्रदर्शनी एवं सूचना केंद्र, अस्थायी थाना, मेडिकल केंद्र, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पेयजल एवं अन्य सुविधाओं, आकर्षक सेल्फी प्वाइंट सहित श्रद्धालुओं के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।

सभी जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने एक स्वर में जिला प्रशासन, बाँका द्वारा श्रावणी मेला-2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु की गई तैयारियों एवं विकास कार्यों की सराहना की।

माननीय मंत्री एवं सहित सभी माननीय अतिथियों ने अपने संबोधन में कांवरिया श्रद्धालुओं के लिए कांवरिया पथ पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक एवं प्रभावी व्यवस्था की गई है।

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों से सेवा-भाव, समर्पण एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आन करते हुए कहा कि श्रावणी मेला में आने वाले प्रत्येक कांवरिया श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम एवं सुखद यात्रा का अनुभव कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला अवधि के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

श्रावणी मेला के उद्घाटन के अवसर पर जिलधिकारी एवं एसपी एवं अन्य अतिथिगण

अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी, बांका श्री अंशुल अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन की प्रथम एवं सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक कांवरिया श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम एवं उत्कृष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से संपूर्ण कांवरिया पथ पर दंडाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा इसकी नियमित रूप से प्रतिदिन निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए रोस्टर के अनुसार सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कांवरिया पथ पर लगातार साफ-सफाई, कचरा निष्पादन एवं स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक, बांका ने कहा कि श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण कांवरिया पथ एवं मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम एवं आधुनिक तकनीकी संसाधनों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे सेवा-भाव, संवेदनशीलता एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ श्रद्धालुओं की सहायता करें तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न होने दें।

फीता काटकर मेला का शुभारंभ करते मंत्री

मच पर उपस्थित मंत्री, विधायक, डीएम और एसपी

बांका-धनबाद बोल बम सेवा शिविर का शुभारंभ

शिवभक्तों की सेवा को समर्पित आयोजन

संतोष कुमार सिंह नगर परिषद के पूर्व चेयरमेन ने फीता काटकर किया शुभारंभ

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ

बांका जिले के कटोरिया के कांवरिया पथ पर श्रावणी मेले के पावन अवसर पर बांका-धनबाद बोल बम सेवा शिविर का संतोष कुमार सिंह पूर्व सभापति नगर परिषद बाका एवं कई गणमान्य के द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य देवघर जाने वाले कांवरियों एवं शिवभक्तों की निस्वार्थ सेवा, सहयोग और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उद्घाटन समारोह में भवानी आईटीआई के निदेशक इंजीनियर निर्मल कुमार, फंटूश बाबू, कौशल बाबू, शंकर चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिविर के सफल संचालन में बबलू कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।श्रावणी यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सेवा का अवसर मिलने पर आयोजकों ने इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताया। इस सेवा कार्य में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सिंह, लोजपा नेता श्री विपिन कुमार सिंह, डॉ. बबलू सिंह तथा लालमोनी बाबा की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा बढ़ाई।आयोजकों ने कहा कि सेवा, समर्पण और श्रद्धा ही इस शिविर की पहचान है। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित एवं सफल हो तथा उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें।बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।

फीता काटकर कर बोलबम सेवा शिविर का शुभारंभ करते संतोष कुमार सिंह एवं अन्य

आयोजक के द्वारा सम्मानित होते संतोष कुमार सिंह

कांवरियों की सेवा करते संतोष कुमार सिंह एवं अन्य अतिथिगण

बच्चों की ट्रैफिकिंग के खिलाफ मुक्ति निकेतन ने चलाया अभियान

दिल्ली में आयोजित बच्चों की ट्रैफिकिंग सेमिनार में भाग लेते चिरंजीव कुमार सिंह अतिथियों के साथ

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ बांका

विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर बांका में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन मुक्ति निकेतन ने बाल तस्करी के खिलाफ निर्णायक अभियान का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से जिले को बाल तस्करी मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान 'नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग' की शुरूआत की गई। इस अभियान में देशभर के सैकड़ों बाल अधिकार संगठनों ने भाग लिया। मुक्ति निकेतन के सचिव चिरंजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है लिहाजा ट्रैफिकरों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तथा गरीब और हाशिये के परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और ट्रैफिकिंग से मुक्त कराए गए बच्चों का बेहतर पुनर्वास अभियान की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बाल तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसे समाज, प्रशासन और नागरिकों की संयुक्त भागीदारी से ही रोका जा सकता है। मुक्ति निकेतन ने लोगों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि बांका को बाल तस्करी मुक्त जिला बनाया जा सके।

सेमिनार में उपथित विभिन्न राज्यों से आये अतिथिगण

समाजसेवी जवाहर कुमार झा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, संगठन होगा मजबूत

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ

बांका बिधानसभा के पूर्व निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी और युवा समाजसेवी जवाहर कुमार झा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और संगठन में उनका स्वागत किया।कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जवाहर कुमार झा ने कहा कि वे पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प जताया। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जवाहर कुमार झा के पार्टी में शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि एक युवा समाजसेवी के रूप में उनकी पहचान और जनसंपर्क का लाभ कांग्रेस को मिलेगा तथा जिले में पार्टी का जनाधार और संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा। लिहाजा, कांग्रेस नेतृत्व ने जवाहर कुमार झा के उज्वल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हुए उनके पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई है।

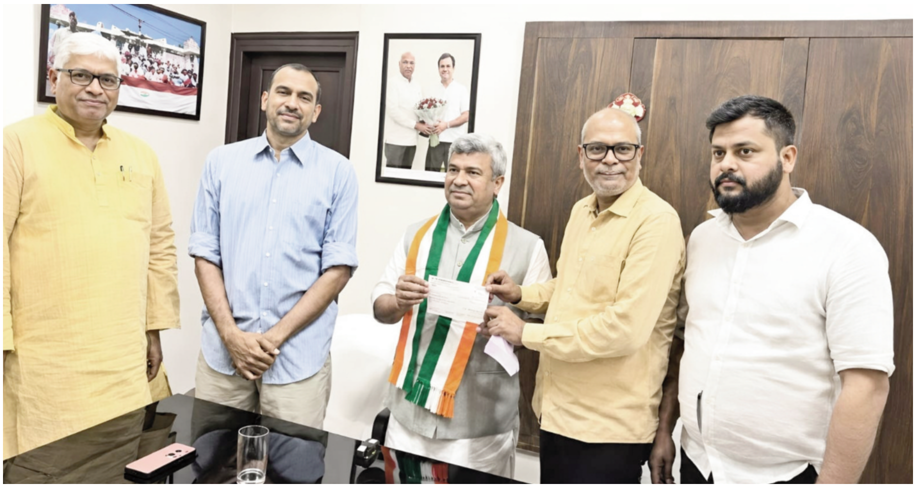

कांग्रसे के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा सदस्याता ग्रहण करते जवाहर कुमार झा

बांका जिलाध्यक्ष से सम्मानित होते जवाहर कुमार झा

अभिनंदन समारोह में शामिल जवाहर कुमार झा

अभिनंदन समारोह को संबोधित करते जवाहर कुमार झा

बांका जिलाध्यक्ष से सम्मानित होते जवाहर कुमार झा

श्रावणी मेला में कांवरिया पथ पर उमडा भक्तों का जन सैलाब : जिला प्रशासन मुस्तैद

दीप प्रज्वलित कर मेल का शुभारंभ करते मंत्री, विधायक, जिलाधिकारी एवं एसपी

राजेश पंजिकार (ब्यूरो चीफ)

बांका जिले में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जिले के कटोरिया स्थित कांवरिया पथ पर शिवभक्तों का जनसैलाब लगातार बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर की ओर बढ़ रहा है। हर ओर "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है।

कंधे पर कांवर और हाथों में श्रद्धा का संकल्प लिए लाखों कांवरिया अजगैबीनाथ धाम से उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए उत्साह और भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिन हो या रात, कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं का कारवां निरंतर जारी है।वहीं, बांका जिला प्रशासन भी कांवरियों की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मार्ग पर पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, विश्राम स्थल, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चौबीसों घंटे संचालित की जा रही हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्रद्धा, सेवा और सुव्यवस्था का अद्भुत संगम बना यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला एक बार फिर आस्था की नई मिसाल पेश कर रहा है।

बाबाधाम जाते कांवरियों का जत्था

मिथिलांचल का पवित्र पर्व मधु श्रावणी पर्व का हुआ शुभारंभ: नव विवाहिता कर रही हैं पूजन

राजेश पंजिकार ब्यूरो चीफ बांका

भागलपुर बांका जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में मिथिला और मिथिलांचलका के परंपराओं से जुडा, नवविवाहिताओं का पावन पर्व मधुश्रावणी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

धार्मिक मान्यताओं के आधार पर यह पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तक मनाया जाता है। लिहाजा इस वर्ष यह पर्व 3 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा।इसी क्रम में तिलकामांझी न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में निशा पंजिकार*और बौंसी में साक्षी पंजिकार कर रही है मधु श्रावणी पूजा। इस पर्व को लेकर नवविवाहित महिलाओं में खासा उत्साह है।मधुश्रावणी मिथिला की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रमुख पर्व है।

ववाह के प्रथम वर्ष में नवविवाहिताएं 13 दिनों तक मां गौरी, भगवान शिव और नाग देवता की पूजा कर पति की दीघार्यु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।

इस दौरान महिलाएं बिना नमक का अरवा भोजन करती हैं, पारंपरिक वेशभूषा में मधुश्रावणी गीत गाती हैं और बुजुर्ग महिलाओं से " मधु श्रावणी की कथा सुनती है इस पर्व की विशेष परंपरा "*मधुश्रावणी-भारो" है, जिसमें नवविवाहिता के ससुराल से मधु श्रावणी पूजन के लिए पूजा सामग्री, वस्त्र, पकवान और मिठाइयां मायके भेजी जाती हैं। वहीं, अंतिम दिन "टेमी" देने की रस्म के साथ इस पर्व का समापन होता है।

श्रावण मास कांवड़ यात्रा, श्रावणी मेला, स्वतंत्रता दिवस,
जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

जवहर झा

उपाध्यक्ष
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी

श्रावण मास कांवड़ यात्रा, श्रावणी मेला, स्वतंत्रता दिवस,
जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

विकास कुमार निराला

भावी मुखिाया प्रत्याशी
ग्राम पंचायत - दक्षिणी कोझी, प्रखंड- फुल्लीडुमर जिला - बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

भीष्म नारायण

डायरेक्टर
आइडियल होली मिशन आवासीय विद्यालय
कटोरिया, बांका, मो. 9661264318

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर
पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

राजीव नन्दन

प्रधान लिपिक
सिविल सर्जन कार्यालय
बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर
पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पंकज कुमार दास

वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर - 10
नगर परिषद, बांका, मो. :
9934757956

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अजय कुमार दास

पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. संजय कुमार सिंह

B.A.M.S (Patna)
शास्त्री चौक
विश्वकर्मा मंदिर के सामने
बांका-9534603144

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अजय कुमार

संगणक, जिला कुष्ठ निवारण कार्यालय, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

बैद्यनाथ प्रसाद

प्रधान लिपिक
एसीडीएमओ
कार्यालय, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

विनय कुमार

लेखापाल
एसीडीएमओ
कार्यालय, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ योगेन्द्र प्रसाद यादव

सामाजिक कार्यकर्ता
ग्राम पंचायत
दक्षिणी कोझी
गोड़ा, जिला बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. सरयू प्रसाद यादव

अध्यक्ष कुसाहा
वन समिति
जिला- बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ बलराम मंडल

दुधारी
बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

आचार्य रघुनंदन शास्त्री

आवासीय मार्शल
एकेडमी, खेसर, बांका,
मो.:8002850364

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

बरुण कुमार सिंह

प्रभारी प्रधानाध्यापक
N P S झिकटा (यादव
टोला) रजौन, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

तुलसी दास

प्रधानाध्यापक
प्रोन्नत मध्य
विद्यालय
कठौन- कटोरिया
जिला -बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

प्रवीण कु. सिंह

लब्ध प्रतिष्ठित उद्घोषक
सह प्रधान शिक्षक
प्राथमिक विद्यालय झखरा,
शंभूगंज

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

मंजूर आलम

प्रो.राज स्टोर
इलेक्ट्रॉनिक
मो.: 9931648300

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

उत्तम कुमार

बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अजय कुमार झा

वरीय लिपिक
एसीडीएमओ कार्यालय, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

प्रदीप कुमार गुप्ता

पूर्व मुखिया

कटोरिया, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

प्रो. (डॉ) हरिकिशोर भारद्वाज

(व्यवस्थापक सह निदेशक)

युग निर्माण मिशन गायत्री विद्यापीठ, नोनिहार, वार्ड - 6, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

संतोष कुमार सिंह

पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

चिरंजीव कुमार

सचिव, मुक्ति निकेतन, कटोरिया (बांका)

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

हेमंत कुमार

जिला निबंधन पदाधिकारी, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

त्रिपुरारी शर्मा

जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

बलवंत कुमार

जिला खनिज पदाधिकारी बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

सूर्य भूषण कुमार

जिला माप तौल पदाधिकारी, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

श्री सुमित्रानंदन

कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

मनोरंजन प्रसाद

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. बिजय कुमार

जिला संचारी रोग पदाधिकारी, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

जितेन्द्र कुमार

M.V.I बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

राजेश कुमार

कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा अमरपुर जिला बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अनुराग कुमार

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत -कटोरिया सह अमरपुर, जिला -बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

कर्पूरी ठाकुर

प्रखंड विकास पदाधिकारी बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

प्रत्यक्ष कुमार

अंचलाधिकारी बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

मनिष कांत

कार्यपालक अभियंता योजना विभाग बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. कुमार रमन

B.D.S (T.M.U) Moradabad U.P

न्यू रौनक मेडिकल हॉल डैम रोड, बौंसी-बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

जय चौहान

प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

कुमारी हेमा

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमरपुर

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

कंचन कुमारी

जिलाध्यक्ष, राजद महिला प्रकोष्ठ बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. दीप्ति सिन्हा

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, अमरपुर

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

क्रांति कुमारी

विशिष्ट शिक्षिका, मध्य विद्यालय सबलपुर, बाराहाट, बांका (बिहार)

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

धर्मेंद्र कुमार सिंह

जनरल सेक्रेटरी

श्री साईं अमर हीरा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, सह- प्रबंध निदेशक, श्री साईं आदर्श नेत्रालय, कटोरिया रोड - बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. विनीता प्रसाद
उपाध्यक्ष, नगर परिषद, बांका

कुमार सेनापति
सामाजिक कार्यकर्ता, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

राहुल कुमार डोकानियां

समाज सेवी
बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पंडित सुबोध नारायण झा

समाजसेवी

देश की आंतरिक सुरक्षा, बिहार का कायाकल्प
और बांका के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित

ग्राम - बढौना जिला - बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

मनीष कु. उर्फ मोनू

जिला उपाध्यक्ष
भाजपा युवा मोर्चा, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

पंकज कु. जय

प्रो.जयप्रकाश
मेडिकल हॉल
पुनसिया
जिला – बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

अमरेन्द्र कुमार साह

प्रो.मंदार प्रिंटिंग प्रेस
तेलिया
बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रंजीत कुमार

प्रोपराइटर

कुमार बीज भंडार अलीगंज, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

आचार्य विश्व स्वरूपानंद अवधूत

प्राचार्य, आनंद मार्ग
हाई स्कूल
आनंदपुर, बांका,
मो.-9932895365

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

मनोज कु. मंडल

दुग्ध व्यवसायी
ग्राम -कल्याणपुर
पोस्ट- दुधारी, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

राजीव कु. यादव

संचालक
ग्राहक सेवा केंद्र
बैंक ऑफ इंडिया
कटोरिया
जिला-बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

विभूति किशोर

विनीत ट्रेडर्स
शकुन्तला मार्केट, काली मंदिर के समीप,
शिवाजी चौक - बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रंजित कु.शर्मा

प्रोपराइटर

शक्ति ग्लास हाउस एंड हार्डवेयर, कचहरी रोड बांका, मो.:- 8084789834

चर्चित बिहार पत्रिका परिवार की ओर से समस्त बिहारवासियों के एवं विज्ञापनदाताओं को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

सुमन अल्ट्रा स्कैन

डॉ. शैलेन्द्र कुमार

M.B.B.S., M.O.C., SPL. Train, (J.L.N.M.C.H.) BGP

चिकित्सा पदाधिकारी

सदर अस्पताल, बांका

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

देविका अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर

आपके क्षेत्र का एकमात्र रंगीन अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर

- Whole Abdomen
- Foetal Well Being
- Upper Abdomen
- Lower Abdomen
- K.U.B.
- Breast + Scrotum

लिंग जांच करना एवं करवाना दंडनीय अपराध है। यहां लिंग जांच नहीं होता है।

मो. : 9122710384

जगतपुर, राम जानकी मंदिर के सामने, बांका

सदर हॉस्पीटल के बगल में

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

साई अल्ट्रासाउण्ड सेंटर

प्रो. अश्वनी कुमार

पी.बी.एस.
कॉलेज के समीप
कटोरिया रोड
बांका
मो.-9204021816

स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

रामचन्द्र गैस एजेंसी

बांका